लखनऊ

गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024

वर्ष : 10 । अंक: 144

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

UPHIN/2014/57034

जीवन में सफलता पाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।

TODAY WEATHER

DAY 27° Hi

NIGHT 12° Low

संक्षेप

अमेरिका ने ईरान के तेल का परिवहन करने वाली 35 कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए

वाशिंगटन । अमेरिका ने ईरान के तेल का अन्य देशों में परिवहन करने वाली 35 कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें भारत की दो कंपनियां भी शामिल हैं। भारत की जिन दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें 'फोनिक्स' का प्रबंधन और संचालन करने वाली 'विजन शिप मैनेजमेंट एलएलपी' और 'टाइटशिप शिपिंग मैनेजमेंट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, लाइबेरिया, हांगकांग सहित अन्य देशों की कंपनियों और जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक बयान में, वित्त विभाग ने कहा कि एक अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद की गई यह कार्रवाई तेहरान पर एक और चोट है। ईरान ने 11 अक्टूबर को लगाए गए प्रतिबंधों के बाद परमाणु कार्यक्रमों को तेज करने की घोषणा की है। आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के कार्यवाहक अवर सचिव ब्रैडली टी स्मिथ ने कहा, ''ईरान अपने पेट्रोलियम व्यापार से होने वाले राजस्व को परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के प्रसार तथा आतंकवादियों पर खर्च कर रहा है, जिससे क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता पैदा होने का खतरा है।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सभी संसाधनों और प्राधिकारों का इस्तेमाल कर इन अवैध गतिविधियों को सरंक्षण देने वाले जहाजों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले के बीच अमेरिका ने मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान का आह्वान किया

वाशिंगटन । अमेरिका ने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों के बीच धार्मिक और आधारभूत मानवाधिकारों सहित मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान का आह्वान किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत लगातार चिंता व्यक्त कर रहा है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संवाददाताओं से कहा, ''हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए।'' पटेल ने कहा, ''सरकारों को कानून के शासन का सम्मान करने की आवश्यकता है, उन्हें आधारभूत मानवाधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। हम इस बात पर हमेशा जोर देते रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''हम इस बात पर बल देते हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनसे अधारभूत मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए।'' इस बीच, अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमन ने एक बयान में कहा, ''बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह पूर्ण दायित्व है कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और हाल में हुए हमलों तथा उत्पीड़न के कारण हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शनों का सार्थक रूप से समाधान करे।'' 'हिंदूएक्शन' के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने निवर्तमान बाइडन-हैरिस प्रशासन से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथियों द्वारा हिंसा को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का आह्वान किया।

मगरमच्छ के आंसुओं से नहीं होगा किसानों का हित, विपक्षी सांसदों पर भड़के धनखड़

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने बुधवार को किसान विरोध का मुद्दा उठाने की विपक्ष की मांग पर आपत्ति जताई और दावा किया कि वे इस मुद्दे का 'राजनीतिकरण' करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इस मांग को मगरमच्छ के आंसू करार दिया, जिससे विपक्षी नेताओं का एक वर्ग सदन से बाहर चला गया। सदन की बैठक शुरू होते ही धनखड़ ने कहा कि वह तमिलनाडु में चक्रवात, किसानों, अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए चर्चा के लिए नोटिस स्वीकार नहीं कर सकते।

विपक्ष ने मांग की कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग पूरी की जानी चाहिए और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के अपनी मांग पर कायम रहने के बावजूद धनखड़ ने कहा कि विपक्ष केवल मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और नाटक कर रहा है। 'मगरमच्छ के आंसुओं से किसानों का हित नहीं पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत के बाद से नियम 267 के तहत दायर कोई भी नोटिस किसानों के मुद्दों से संबंधित नहीं है।

इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल के पास जमा हो गए। कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को धनखड़ की टिप्पणियों का हवाला देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और इसे पूरा क्यों नहीं किया गया।

'हमारी भावनाओं का मुद्दा', भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने उठाया बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन बुधवार को लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा। शून्य काल के दौरान कृष्ण नगरी मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी सहित कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। सदस्यों ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दखल देने का अनुरोध किया और संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन संस्थाव व उसके अनुयायियों पर चरमपंथियों के हमले निंदनीय हैं। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का जिक्र किया और कहा कि इस्कॉन के लोग मानवता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पक्ष में गवाही देने वाले दो लोगों को भी जेल में डाल दिया गया।

'हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश सरकार'

मालिनी ने कहा, मैं खुद कृष्ण भक्त हूं और इस्कॉन की अनुयायी हूं। मैं कृष्ण की पावन नगरी की प्रतिनिधि हूं। हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं का विषय है। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

सांसद अनिल फिरोजिया ने की पीएम से दखल की मांग

वहीं, असम से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित कर बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कार्रवाई करने का संदेश भेजा जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के ही अनिल फिरोजिया ने इस मामले में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने का अनुरोध किया।

एलएसी पर अब कैसा है माहौल, भारत-चीन के रिश्तों में क्या हुई प्रगति : जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बयान दिया। उन्होंने इस दौरान भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की मौजूदा स्थिति की भी जानकारी दी। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ एलएसी पर कुछ हिस्से को लेकर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए भारत और चीन समय-समय पर बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा, 'गलवां घाटी में जून 2020 में हुई झड़प की घटना का भारत-चीन के रिश्तों पर असर पड़ा था। यह 45 वर्षों में पहली बार सीमा पर सैनिकों की जान जाने का मसला नहीं था, बल्कि इसके चलते एलएसी के दोनों तरफ भारी मात्रा में हथियारों की तैनाती हुई थी। जयशंकर ने कहा कि इस बीच तमाम चुनौतियों के बावजूद, हमारे सैन्य बलों ने कोविड काल, रसद की चुनौतियों और भीषण ठंड का सामना करते हुए गलवां घटनाक्रम में समुचित प्रतिक्रिया दी। वे तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाबी तैनाती करने में सक्षम थे।'

जयशंकर ने कहा कि चरण-दर-चरण प्रक्रिया के माध्यम से पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी का काम संपन्न हो गया है, जो अभी देपसांग और डेमचोक में पूरी तरह संपन्न होना है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के संबंध एलएसी की मर्यादा का सख्ती से सम्मान करने और समझौतों का पालन करने पर निर्भर होंगे। उन्होंने कहा, ''हमारे संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। हम स्पष्ट हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास की बुनियादी शर्त है।''

पीएम मोदी-चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात का भी जिक्र किया

चीन के साथ आगे के रिश्तों पर जयशंकर ने कहा कि मुद्दों के समाधान तथा संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। उन्होंने अपनी और चीनी समकक्षों की मुलाकातों को लेकर राज्यसभा को जानकारी दी।

गाजियाबाद बॉर्डर से वापस लौटे राहुल गांधी, संभल जाने की नहीं मिली इजाजत, बोले- ये संविधान ख़त्म करने वाला नया भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर सीमा पर रोक दिया, जिससे हिंसा प्रभावित संभल की उनकी योजनाबद्ध यात्रा अवरुद्ध हो गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रभावित लोगों से मिलने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वह अपना काफिला छोड़कर पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें कुछ दिनों के बाद लौटने के लिए कहा था।

राहुल ने पत्रकारों से कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मना कर रही है, नहीं जाने दे रही। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन वे मुझे रोक रहे हैं। मैं अकेले जाने और पुलिस के साथ जाने को तैयार था, लेकिन उन्हें यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने दावा किया कि वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में लौटेंगे तो वे हमें जाने देंगे। यह विपक्ष और संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ, हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है।

भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि नया भारत है, ये संविधान ख़त्म करने वाला भारत है। ये अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को हिंसा के पीड़ितों से मिलने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वह गलत है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार हैं और उन्हें इस तरह नहीं रोका जा सकता।

प्रियंका ने भी कहा कि उन्हें पीड़ितों से मिलने और जाने की अनुमति पाना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यूपी पुलिस के साथ अकेले जाएंगे लेकिन वे ऐसा करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि वे इतना भी नहीं संभाल सकते। वे इतने अहंकार से क्यों कहते हैं कि उन्होंने कानून-व्यवस्था का ध्यान रखा है? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पुलिस ने हमें सूचित किया कि वे हमें 4-5 दिनों के बाद अनुमति देंगे।

सुखबीर बादल पर हमले की केजरीवाल ने की निंदा, बीजेपी को दी चुनौती, कहा- 2 दिन रुको, मैं बेनकाब कर दूंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। बुधवार को आप नेता अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को टालने के लिए पंजाब पुलिस की सराहना की। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि पंजाब में आज एक घटना घटी, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं।

इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि एक बात तो साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बर्बाद करने और बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे कई बड़ी ताकतें शामिल हैं। आज जिस तरह से पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इस घटना को रोका बल्कि पूरे देश के सामने एक उदाहरण भी पेश किया कि सजगता के साथ कानून व्यवस्था कैसे कायम रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम गोलीबारी हो रही है, पूरी राजधानी गैंगस्टरों के कब्जे में है, हर जगह ड्रग्स बिक रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पूरी भाजपा चुप हो जाती है और उनके शीर्ष नेता कहते हैं कि अपराध कोई मुद्दा नहीं है, दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि जब मैं सीएम था, तो मुझ पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंपने का दबाव डाला गया। जब मैंने इनकार कर दिया, तो मैं सोच रहा था कि शायद इसीलिए मुझे जेल भेजा गया है। बीजेपी को मेरी चुनौती है कि वे घोषणा करें कि अगर वे सत्ता में आए तो बिजली कंपनियों को अडानी को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने (बीजेपी) दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश शुरू कर दी है, मेरे पास सबूत हैं और गवाह। 2 दिन रुको, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। मैं देश को बताऊंगा कि आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में कैसे चुनाव जीता। आपने ईमानदारी से चुनाव नहीं जीता।

भाजपा सरकार को तरक्की, खुशहाली, विकास से कोई मतलब नहीं है : अखिलेश यादव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार को तरक्की, खुशहाली, विकास से कोई मतलब नहीं है। भाजपा का काम समाज में नफरत फैलाना, संविधान विरोधी काम करना, लोकतंत्र की हत्या करना है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जनता को वोट नहीं डालने दिया। यूपी का उपचुनाव पहले 13 नम्बर 2024 को होना था, जब भाजपा को जानकारी हो गयी कि बहुत सारे लोग त्योहारों में अपने गांव आये थे और वे वोट डालकर वापस जाएंगे तो भाजपा ने उपचुनाव की तारीख बदलवा कर 20 नवम्बर 2024 करा दी।

कहा कि 19 तारीख को आनन-फानन में संभल में सर्वे कराकर तनाव बढ़ाने और माहौल खराब करने का प्रयास किया, जब उस दिन सब कुछ शांत रहा तो फिर षडयंत्र के तहत दोबारा सर्वे की योजना बनायी। चुनाव में हुई धांधली की पोल न खुल जाये इसके लिए भाजपा ने संभल की घटना करायी। भाजपा की ये सत्ता भूख की लड़ाई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि दोबारा सर्वे के दौरान जा रही टीम के साथ जो लोग नारे लगाते जा रहे थे, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। भाजपा सरकार किसी भी दल के नेता को संभल नहीं जाने दे रही है, आखिर सरकार क्या छिपाना चाह रही है। संभल जाने पर प्रतिबंध लगाना सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। संभल में सौहार्द शांति का माहौल बिगड़ा तो उसके लिए भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह चुरा सकती है। सबूतों, तथ्यों, माहौल को देखने पर सबको नजर आएगा कि ये हिंसा प्रायोजित थी और सारा कांड साजिशन हुआ। भाजपा का झूठ कब तक सच पर पर्दा डालेगा? अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में प्रशासन और अधिकारी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहें हैं? क्या लोकतंत्र में अधिकारी इस तरह की भाषा और व्यवहार कर सकते है? उन्होंने कहा कि संभल में प्रशासन पीड़ितों को न्याय नहीं दे रहा है।

नतीजों से साफ, एक हैं तो सेफ हैं... विधायक दल का नेता चुने जाने पर बोले फडणवीस, शिंदे का किया धन्यवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। पार्टी की अहम बैठक में देवेन्द्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता और प्रभावी तौर पर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। इस कदम ने फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी के एक कदम और करीब ला दिया है, पिछले महीने के विधानसभा चुनावों में शानदार जनादेश हासिल करने के बाद पार्टी को अपना राज्य प्रमुख मिलने की उम्मीद है। भगवा पार्टी ने पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को अपने महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

जैसे ही भाजपा नेताओं ने सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को अपने विधायक दल का नेता चुना, 'देवा भाऊ तुम आगे बढ़ो' के नारे लगाए गए। फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा कि मैं विधायक दल के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे चुना। मैं हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षकों विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऐतिहासिक चुनाव थे और इन चुनावों ने साबित कर दिया है कि 'एक है तो सेफ है' और 'मोदी है तो मुमकिन है'।

भाजपा नेता ने कहा कि हमने हरियाणा के साथ अपनी जीत का सिलसिला फिर से शुरू किया है और अब महाराष्ट्र ने इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि मैं पूरी तरह से महाराष्ट्र के मतदाताओं के सामने नतमस्तक हूं। मैं सीएम एकनाथ शिदने और डिप्टी सीएम अजित पवार और हमारे अन्य सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगले दिनों में कुछ चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप होंगी और कुछ चीजें हमारी इच्छा के विपरीत होंगी, लेकिन हम सभी को राज्य और देश के व्यापक हित में काम करना है। हम महाराष्ट्र की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले बुधवार को कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और फडणवीस मौजूद थे। भाजपा ने सीतारमण और रूपाणी को पार्टी की महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि महायुति के सहयोगी दल बुधवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

हवाई यात्रा महंगा होने का मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया, बोले, प्लेन से ट्रेन पर लौटने को मजबूर हुए लोग

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने हवाई यात्रा महंगा होने का मामला संसद में उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों को भी हवाई यात्रा कराने लायक सिस्टम बनाने का दावा किया था, लेकिन हवाई टिकटों की महंगाई से आम आदमी अब प्लेन छोड़कर ट्रेन से यात्रा करने में सफर करने के लिए मजबूर हो गया है।

राघव चड्ढा ने संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए कहा कि सिर्फ एक साल के भीतर हवाई यात्रा के किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ा है। दिल्ली से मुंबई और पटना जैसे सामान्य रूट्स पर टिकटों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में टूरिज्म का विकास करने की बात कहती है, लेकिन इस तरह की महंगाई से लोग हवाई यात्राओं से दूर हो रहे हैं। इसका सीधा असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ेगा। चड्ढा ने कहा कि देश के एयरपोर्ट्स की हालत बस अड्डों से भी बदतर हो गई है। लंबी लाइनों, भीड़भाड़, और खराब प्रबंधन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा को लग्जरी ट्रेवल बनाने की बजाय आम यात्री के लिए सुलभ बनाना है। एयरपोर्ट्स पर महंगे खानपान का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर पानी की बोतल 100 रुपए की मिल रही है। एक कप चाय के लिए भी 200-250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

भाकियू का नोएडा कूच: पुलिस ने रोके वेस्ट यूपी के किसान, जमकर हंगामा-कहासुनी, कई कार्यकर्ताओं को किया नजरबंद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मेरठ। ग्रेटर नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल से किसानों को हटाकर जेल भेजे जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन ने आज ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर महापंचायत बुलाई है। इसमें यूनियन के नेता राकेश टिकट के भी शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि उन्हें अलीगढ़ में ही पुलिस ने नोएडा जाने से रोक दिया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान एकत्र होकर नोएडा के लिए रवाना हुए। लेकिन पुलिस ने उन्हें नोएडा जाने से रोक दिया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर व सहारनपुर से निकले किसानों को पुलिस ने टोल पर ही रोक लिया। वहीं किसान टोल पर ही धरना देकर बैठ गए।

सिसौली में पंचायत के बाद हुआ नोएडा कूच का एलान

दरअसल, यूनियन के पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष पवन खटाना और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ अन्य किसानों को जेल भेजने की खबर संगठनों के हाई कमान तक पहुंच गई। इसके बाद राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर शाम 4:00 बजे सिसौली में सभी जिला अध्यक्षों समेत पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में विचार करने के बाद महापंचायत बुलाने का फैसला लिया गया। इसमें राकेश टिकैत, भाकियू पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों समेत अन्य किसान नेताओं के पहुंचने की बात कही गई।

पांच मंडल के किसानों को ग्रेटर नोएडा पहुंचने का आह्वान

संयुक्त किसान मोर्चा के हवन पर भागने प्रदेश के पांच मंडल सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ आगरा और मुरादाबाद के किसानों के साथ आज ग्रेटर नोएडा कूच करने का एलान कर दिया था। मेरठ और सहारनपुर मंडल के किसान परतापुर में एकत्र होकर नोएडा जाने के लिए निकले तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान किस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने पश्चिमी यूपी के विभिन्न शहरों में बड़े किसान नेताओं को उनके घर पर और आवास पर ही नजर बंद कर दिया।

संगठन कमजोर हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा

भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का कहना है कि किसानों के सामने मुश्किल हालात हैं। खाद, बिजली, मजदूरी के रेट बढ़ रहे हैं। फसलों के उत्पादन में खर्च बढ़ गया है, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं हर साल गन्ने की फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे। किसान संगठन कमजोर हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। सभी को भेदभाव भुलाकर आंदोलन करना होगा। आंदोलन की कमजोरी किसानों की हार होगी।

किसान भवन पर आयोजित पंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि 10 बीघा जमीन के मालिक को नौ बीघा जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। हाईवे, आवासीय कॉलोनी के नाम पर किसानों की महंगी जमीन छीनी जा रही है। भेदभावपूर्ण मुआवजा दिया जा रहा है।

मुजफ्फरनगर में भंगेला चेकपोस्ट पर रोके गए किसान

मुजफ्फरनगर में नोएडा के किसान आंदोलन में भाग लेने जा रहे किसानों को खतौली के भंगेला चेकपोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया। नाराज किसान धरने पर बैठ गए। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। दिल्ली-दून हाईवे पर जाम लग गया।

भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में किसान भंगला पहुंचे। एसडीएम बुढ़ाना मोनालिसा जौहरी और सीओ खतौली रामाशीष यादव भी पुलिसबल के साथ पहुंच गए। किसानों को नोएडा जाने से रोक दिया। इस दौरान किसान हाईवे पर ही धरना देकर बैठ गए। किसानों का कहना था कि उन्हें नोएडा जाने से रोका जा रहा है। करीब आधे घंटे तक हंगामे के बाद पुलिस ने किसानों को आगे के लिए रवाना कर दिया।

सहारनपुर में सुबह से ही अलर्ट हो गई पुलिस

सहारनपुर में छुटमलपुर में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए नोएडा कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को पुलिस प्रशासन ने चमारीखेड़ा टोल प्लाजा पर रोक लिया। सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चौधरी रघुवीर सिंह और जिला अध्यक्ष नरेश स्वामी का काफिला फतेहपुर थाना क्षेत्र में चमारी खेड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचा तो यहां पहले से ही तैनात एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह और सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने उन्हें रोक लिया।

बागपत में पुलिस अलर्ट, कई नेताओं को नजरबंद किया

नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर महापंचायत को सफल बनाने के लिए बागपत जिले से भाकियू कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पुलिस ने नजरबंद किया। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली एनसीआर के महासचिव प्रदीप धामा को बागपत के राष्ट्र वंदना चौक से पुलिस ने घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। इसके आलावा मविकलां, ढिकौली, अग्रवाल मंडी टटीरी से भी कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया।

नजीबाबाद में किसान नेताओं को घर पर किया नजर बंद

संयुक्त किसान मोर्चा के ग्रेटर नोएडा कूच आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं को पुलिस ने देर रात उनके घर पर ही नजर बंद कर दिया। किसानों नेताओं ने कहा कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा नियोजित मांगों के आगे वह सरकार के किसी दबाव में नहीं आएंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गांव चमरौला निवासी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सचिव दिनेश कुमार, गांव सराय आलम निवासी ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश कुमार और शहजादपुर निवासी अजय कुमार को मंगलवार की देर रात नांगल पुलिस ने उनके घरों पर नजर बंद कर दिया। रति लगभग एक बजे पुलिस ने किसान नेताओं को ग्रेटर नोएडा कूच करने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद नजरबंद किया।

किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की न्यायोचित मांगों को दबाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए जाने से जबरन रोका जा रहा है।

खून के छींटों से मिला घर का रास्ता...अपनी करतूत और पहचान छुपाई, बेगुनाह मासूम की ठंड से गई जान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। अपनी करतूत और पहचान छिपाने के लिए वह कर दिया, जिससे एक बेगुनाह मासूम की जान चली गई। मामला गोरखपुर के बांसगांव थाना इलाके के एक गांव का है। सोमवार भोर में झाड़ियों में फेंकी गई नवजात बच्ची मिली।

उधर से गुजर रहीं गांव की महिलाएं रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचीं और उसे उठा लिया। शंका के आधार पर एक घर में गईं तो पता चला कि नवजात को 19 साल की अविवाहित युवती ने जन्म दिया है।

युवती की हालत खराब देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जच्चा-बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया। युवती के परिजनों के अनुसार, लोकलाज के डर से नवजात को प्रसव के बाद फेंक दिया था। जानकारी के मुताबिक, युवती का गांव के ही एक स्वजातीय युवक से संबंध था। इस बारे में युवती के परिजनों को जानकारी नहीं थी। युवती के गर्भवती होने पर परिजनों को जानकारी हुई तो उसे घर में कैद कर दिया। नौ माह बाद सोमवार को युवती के पेट में दर्द उठने पर परिजनों ने घर पर ही प्रसव कराया। इसके बाद परिजन ठंड में नवजात को बिना कपड़ों के ही गांव में झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने मां और बच्चे को पीएचसी पर भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बांसगांव पुलिस ने मामले में एक युवक से पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि परिजन अभी अस्पताल में हैं। तहरीर देते हैं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को युवती ने बताया कि घर पर जब परिजनों को पता चला कि वह गर्भवती है तो कई बार उसे मारने का प्रयास किया गया।

एक जानकार ने बताया कि बच्चे पर खतरा होने पर मां के जीवन पर संकट आ सकता है। तब पेट छुपाने के लिए चार माह तक घर से बाहर नहीं निकली। रविवार रात उसे दर्द शुरू हो गया। प्रसव के बाद बच्ची को देख भी नहीं पाई थी। बच्ची ने इलाज के दौरान मंगलवार भोर में दम तोड़ दिया।

खून के छींटों से मिला घर का रास्ता

बांसगांव में जन्म के बाद ही नवजात बच्ची को पांच फीट ऊंचाई से झाड़ियों में फेंक दिया गया। दर्द से तड़पती बच्ची इस ठंड में करीब एक घंटे तक झाड़ियों में रोती रही। शुक्र था कि जानवरों से पहले इंसान की नजर उसपर पड़ गई। जिला अस्पताल में नवजात और उसकी मां को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सोमवार भोर में पांच बजे गांव की कुछ महिलाओं ने झाड़ी में रोने की आवाज सुनी। देखा तो नवजात बच्ची रो रही थी। महिलाओं ने बच्ची को उठाया। इसी दौरान उनकी नजर अचानक खून के छींटों पर पड़ी। इसके आधार पर वह आगे बढ़ीं तो एक घर के पास खून से ही सने कुछ कपड़े फेंके हुए नजर आए। अंदर जाकर पूछा तो एक महिला ने पहले तो इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद नवजात को स्वीकार कर अपने साथ ले गई। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस घर में गई तो एक युवती बिस्तर पर लेटी थी। उसे रक्तस्राव हो रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पीएचसी पहुंचाया। यहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश

कर्नलगंज(गोण्डा)। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर शिक्षक,शिक्षिकाओं को बदनाम करने की साजिश की शिकायत पुलिस से की गई है। कोतवाली कर्नलगंज अन्तर्गत नगर क्षेत्र में संचालित एक विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सामूहिक रूप से कोतवाली में तहरीर दी है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय की छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर इंस्टाग्राम पर विद्यालय के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। उसके बाद शिक्षक-शिक्षिकाओं की फोटो अपलोड करके अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही नहीं, उनके फोटो के साथ अश्लील शब्द, गाली व धमकी भरे पोस्ट करके परेशान कर रहा है। उसके इस कृत्य से शिक्षक-शिक्षिकाएं परेशान हैं, समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही है। शिक्षक-शिक्षिकाओं ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

प्रेमी जोड़े ने पहले खाया जहर, फिर लेट गए ट्रेन की पटरी पर, मिलने नहीं देते थे परिजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मिर्जापुर। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र के जमुई आरडीएस के सामने रेलवे लाइन पर बुधवार की भोर में तीन बजे ट्रेन से कटकर प्रेमी-प्रेमिका ने जान दे दी। सूचना पर पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। क्षेत्र के रैपुरिया निवासी राजकुमार (25) युवती सपना (16) से प्रेम करता था। अप्रैल माह में लड़की के परिजनों ने युवक पर पुत्री को बहला कर भाग ले जाने का आरोप लगाया था। दोनों शादी करना चाहते थे, पर परिवार के लोग राजी नहीं थे। इसके बाद बुधवार की भोर में दोनों जमुई रेलवे लाइन के पास पहुंचकर पहले विषाक्त सेवन किया फिर ट्रेन से कटकर जान दे दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को करने में लेकर परिजनों को सूचना दिया। चुनार थानाध्यक्ष रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि अप्रैल माह में लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। प्रेम संबंधों में दोनों ने जान दी है। रेलवे लाइन के पास जहर की शीशी मिली है। इससे लग रहा है कि पहले विषाक्त सेवन किया है । उसके बाद ट्रेन से कटकर जान दी है । शव आपको पोस्टमार्टम के लिए भेज कर कार्रवाई की जा रही है।

हुसैनिया नौतामीर अमहट में शबीह ताबूत का जुलूस आज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुलतानपुर। मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाबे फातमा जहरा के शहादत के मौके पर 3दिसम्बर से 6दिसंबर 2024तक सुलतानपुर के सभी शिया इलाकों में मजलिस का दौर जारी है।तुराबखानी के इमाम बाड़े में मजलिस मौलाना इमाम हैदर बम्बई ने खेताब किया ।

आज रात 8बजे अंजुमन असगरिया अमहट की तरफ से हुसैनिया नौतामीर अमहट में एक मजलिस होगी जिसमें पेशख्वानी जोहेर अकबरपुरी आरिफ रजा लखनऊ अंसार सुलतानपुरी आबिस रजा सुलतानपुरी संचालन मौलाना फैज अब्बास मौलाना जीशान हैदर करेंगे और मजलिस मौलाना रेहान हैदर जैदी आस्ट्रेलिया पढ़ेंगे इसके बाद अमहट की सभी अंजुमने नौहा मातम करेंगी और जनाबे फातमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के शबीह ताबूत का जुलूस हुसैनिया नौतामीर से उठकर जामा मस्जिद अमहट पर खत्म होगा दौराने जुलूस मौलाना मोहम्मद जाफर खान मौलाना मौलाना सैयद मोहम्मद आबिद मुजफ्फर नगर तकरीर करें गे मंगलवार की रात में मौलाना जायर हसन की तरफ से हुसैनिया बादल खां अमहट में एक मजलिस हुई जिसे मौलाना सैयद तहकीक हुसैन रिजवी गुजरात ने खेताब 'पढ़ा' किया उन्होंने कहा कि जनाबे फातमा जहरा मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी थीं जिसे मोहम्मद साहब अपने दिल का टुकड़ा कहते थे जब फातमा जहरा की शादी का समय आया तो खुदाने मोहम्मद साहब को आदेश दिया कि फातमा की शादी मेरे आदेश से होगी और खुदा ने कहा ऐ मेरे पैगम्बर अरब के लोगों से कहदो कि एक निर्धारित समय पर आसमान से एक तारा उतरेगा जिसके घरपर उतरेगा उसी के साथ फातमा की शादी होगी। इस प्रकार अरब के लोग अपना घर सजाये बैठे थे आसमान से सितारा चला और पूरे अरबका चक्कर लगाता हुआ अली के घरपर उतरा और फातमा जहरा की शादी मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ हुई जनाबे फातमा जहरा की माँ का नाम जनाबे खदीजतुल कुबरा था जो अरब की मलका थीं जिना अरब में शासन था ।यह जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुलतानपुर ने दी है।

शासन की मंशानुरूप होगा जनहित कार्य का कार्य: गामिनी सिंगला

बल्दीराय/सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील के पीरोसरैया ग्रामसभा में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें जनहित की समस्याओं को सुनकर निस्तारण की कार्यवाही की गई। बल्दीराय की उपजिलाधिकारी आईएएस गामिनी सिंगला की अध्यक्षता में ग्राम सभा में चौपाल का आयोजन हुआ ।जिसमें तहसीलदार अरविंद त्रिपाठी की देखरेख में गांव की समस्या,गांव में ही समाधान के तहत ग्रामवासियों की तमाम समस्या के शिकायतपत्रों की जांच हुई और उनके समाधान के लिए मातहतों को तत्काल निर्देशित किया। उपजिलाधिकारी ने हल्का लेखपाल क साथ कसेहिया ग्राम में अतिक्रमित चकमार्ग व रिजर्वलैंड गाटा संख्या 1212 तालाब व 1222 जंगलझाडी की अतिक्रमित जमीन का चिन्हांकन करवाया। बता दे कि ग्रामसभा में बड़ी संख्या में करोड़ों की जमीन पर दंबगो का अवैध कब्जा है।

गैस सिलेंडर का रेगुलेटर फटने से हुआ हादसा... तीन लोग आग में झुलसे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गैस सिलेंडर का रेगुलेटर फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में तीन लोग बुरी तरह झुलस गए और आग की चपेट में आ गए। हादसे के दौरान तीनों लोग खाना बना रहे थे। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की ही हालत नाजुक बनी हुई है। आग की चपेट में आने से तीनों बुरी तरह जल गए हैं।

जिस समय ये हादसा हुआ। उस वक्त घर पर पांच लोग मौजूद थे। तीन लोगों के आग में झुलसने के बाद तुरंत उन्हें लखनऊ में बीकेटी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तीनों ही शख्स बुरी तरह जले हुए हैं। तीनों के हाथ और पैरों का बुरा हाल हो गया है। तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये हादसा कैसे हुआ। इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन गैस सिलेंडर का रेगुलेटर फटने आग लगी थी।

पांच लोगों की हुई थी मौत

अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जब गैस सिलेंडर फटने से बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग में झुलसे लोगों की हालत काफी खराब है। हाल ही में एक खबर जयपुर से सामने आई थी, जहां एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई थी। एलपीजी सिलेंडर विस्फोट से हादसा हुआ था।

लीकेज से हुआ था बड़ा हादसा

जयपुर में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में परिवार के 5 लोगों की जान गई थी। बताया गया था कि फॉल्टी इंस्टॉलेशन की वजह से लीकेज हुई थी, जिसके बाद भीषण हादसा हो गया था। हालांकि 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन पांच लोग इसमें झुलसकर पहले ही अपनी जान गवां चुके थे। इस हादसे में एक परिवार तबाह हो गया था।

गिड़गिड़ाती रही वो... फिर भी पति पर बरसा दीं गोलियां, इसलिए घर में आग लगाकर की अधेड़ की हत्या

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। गोरखपुर के गीडा इलाके के अमटौरा गांव में साइकिल हटाने के विवाद में मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले मनबढ़ों ने घर पर चढ़कर शिवधनी निषाद (55) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घर के बाहर छप्पर में आग लगाकर फरार हो गए। वहीं बीच-बचाव में आईं शिवधनी की पत्नी हेमलता के बाएं हाथ में भी गोली लग गई है। महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इधर, हत्या के बाद गांव में दहशत है।

घटना की सूचना मिलते ही गांव में सीओ गीडा प्रशाली गंगवार ने पुलिस फोर्स संग पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किया। इसके बाद एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने भी घटनास्थल पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की। परिजनों और ग्रामीणों से मिलकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गीडा पुलिस ने अमटौरा निवासी मुख्य आरोपी शशि शंकर उर्फ पिकलू सिंह समेत पांच नामजद आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 312 बोर के लाइसेंसी असलहे से घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है।

अमटौरा गांव निवासी शिवधनी निषाद के घर सोमवार को मुंडन कार्यक्रम था। इस दौरान रास्ते में खड़ी साइकिल हटाने को लेकर पड़ोस में रहने वाले शिवधनी से मनबढ़ आरोपी विवाद करने लगे। मनबढ़ों ने शिवधनी को पीट भी दिया। इसमें शिवधनी को चोटें आई थीं। रात के समय ही थाने पहुंचकर उन्होंने तहरीर दी। मंगलवार सुबह बुलाकर पुलिस ने मेडिकल कराया।

अपराह्न तीन बजे वह वापस आए तो तहरीर देने से नाराज मनबढ़ों ने घर पर चढ़कर शिवधनी को गोली मार दी। इस दौरान बीचबचाव में आई पत्नी के हाथ में भी गोली लग गई। मनबढ़ों के फरार होने के बाद दंपती को पीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवधनी को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लग गई है।

गिड़गिड़ाती रही वो... फिर भी पति पर बरसा दीं गोलियां

गीडा इलाके के अमटौरा गांव में सोमवार रात से ही विवाद सुलग रहा था। बताया जा रहा है कि जब मनबढ़ों ने शिवधनी पर बंदूक तान दी तो पत्नी हेमलता आगे आ गईं। वह काफी गिड़गिड़ाईं , लेकिन मनबढ़ नहीं पसीजे और शिवधनी को गोली मारकर उनकी जान ले ली। गांव में घटना से एक दिन पहले सोमवार रात मुख्य आरोपी शशि शंकर उर्फ पिकलू सिंह ने विवाद के बाद शिवधनी के सीने में दांत से काट लिया था।

आरोप है कि दूसरे दिन मंगलवार को जब शिवधनी पीएचसी से मेडिकल कराकर लौटे तो उनके घर पर अपने साथियों के साथ चढ़कर पिता की लाइसेंसी बंदूक से शिवधनी के गले में गोली मार दी। गांव में दहशत फैलाने के लिए उसने गोली मारने के बाद छप्पर में आग भी लगा दी। यह भी चर्चा है कि आरोपी की चाची पर शिवधनी ने पहले हमला कर दिया था, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई थीं। इसका बदला लेने के लिए आरोपी ने उन्हें गोली मार दी।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब गोली चलाने के लिए पिकलू ने बंदूक तानी तो उसकी नाल पकड़कर आगे हेमलता ने अपना हाथ लगा दिया था। लेकिन गोली उनके हाथों को चीरते हुए पति शिवधनी के गले में जाकर लग गई। इस दौरान पत्नी हेमलता के हाथ में भी छर्रे लग गए। शिवधनी के चार बच्चे अभिषेक, विकास, सुमन और पूनम हैं। बड़े बेटे अभिषेक ने पांच नामजद आरोपियों अमटौरा निवासी शशिशंकर सिंह उर्फ पिकलू, उसके भाई एटम सिंह के साथ ही सचिन सिंह, अजय सिंह और विजय सिंह के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने देर रात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। देर रात में ही पोस्टमार्टम कराया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर गीडा पुलिस पूछताछ कर रही है।

पटीदार के घर था मुंडन कार्यक्रम

शिवधनी के पटीदार लग्गन के लड़के का सोमवार को मुंडल कार्यक्रम था। सटे घर होने से शिवधनी का पूरा परिवार भी लगा हुआ था। मुंडन में आए मेहमानों ने सड़क पर ही बाइक और साइकिल खड़ी की थी। रात करीब आठ बजे आरोपी पिकलू वहां आया और बोला कि थोड़ी देर में बाइक और साइकिल हटा लो। इसको लेकर आरोपी ने घर की एक बुजुर्ग महिला को अपशब्द कह दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। तभी शिवधनी और उसके परिवार पर पिकलू ने हमला बोल दिया।

परिवार से मिलकर विधायक ने दिया हर संभव मदद का भरोसा

चौरीचौरा के विधायक ई. श्रवण निषाद अमटौरा गांव पहुंचे। वहां मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी की जगह जेल में है, उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी, जल्द ही गिरफ्तारी होगी और परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। विधायक ने सीओ गीडा से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा।

घबराइए मत, हर शिकायत पर कराएंगे प्रभावी कार्रवाई : सीएम योगी

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, 'घबराइए मत, हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। हर पीड़ति की समस्या का समाधान कराया जाएगा। सरकार सबकी समस्या दूर करने को संकल्पित है।' जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ति व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं।

गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। एक-एक कर और इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनीं। उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश भी दिए कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ति को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए।

जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए जिससे उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

निलंबित ट्रैफिक सिपाही ने एप से डिलीट किए 100 से अधिक चालान, निदेशालय की आईडी से किया खेल, मुकदमा दर्ज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक निलंबित ट्रैफिक सिपाही ने अपने ही विभाग से खेल कर दिया। निदेशालय की ई- मेल आईडी का इस्तेमाल कर ट्रैफिक सिपाही अजय शर्मा ने गलत तरीके से 116 चालान कर डिलीट कर दी। इनमें से कुछ कोर्ट से रिलीज भी किए गए हैं। गड़बड़ी का खुलासा होने पर आरोपी सिपाही के खिलाफ ट्रैफिक लाइन के आईटी सेल प्रभारी आनंद कुमार की तहरीर पर आरोपी सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश चल रही है।।

पुलिस से की गई शिकायत में ट्रैफिक लाइन लखनऊ के आईटी सेल प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि 25 अक्टूबर को उन्नाव से सिपाही मुकेश राजपूत ने लखनऊ ऑफिस में कार्यरत आदित्य दुबे को सूचना दी थी।

उसने बताया कि 24 अक्टूबर 2024 को गाड़ी नंबर यूपी 35 क्यू 7005 का चालान यातायात निदेशालय की यूजर आईडी संख्या uptp@nic.in से गलत तरीके से डिलीट किया गया। जबकि ये सारे काम यातायात निदेशालय से नहीं होते हैं बल्कि एनआईसी से किए जाते हैं। संदेह होने पर एनआईसी से जानकारी मांगी गई। जानकारी में पता चला कि इस आईडी से अब तक करीब 116 चालान गलत तरीके से डिलीट और कोर्ट से रिलीज किए गए हैं।

जांच में सामने आया सिपाही का खेल

विभाग ने जब आंतरिक जांच कराई तो पता चला कि आईटी सेल में कार्यरत सिपाही अजय शर्मा ने बिना किसी अधिकारी को बताए निदेशालय की यूजर आईडी का इस्तेमाल कर ये चालान डिलीट कर दिए। इनमें से कुछ को कोर्ट से भी रिलीज कराया। अधिकारियों ने बताया कि अजय शर्मा मौजूदा समय में निलंबित है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में आरोपी अजय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कुल चालानों की कीमत कितनी थी। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी ने कहा कि विवेचना की जा रही है इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

विधायक खेल स्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी सरकार : मुख्यमंत्री

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल की गतिविधियों को ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खंड और विधानसभा स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार सांसद खेल स्पर्धा की तर्ज पर विधायक खेल स्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए विधायको का आह्वान किया जाएगा। गांव से लेकर विधानसभा स्तर तक होने के बाद इस स्पर्धा को जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

सीएम योगी बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के द्वितीय संस्करण के शुभारंभ एवं षष्ठम ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइजमनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन-पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीण खेल लीग की मशाल को गत लीग में दो गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलेटिक खिलाड़ी अभय को सौंपकर लीग के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया और कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल से सबको खेलने, फलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। जो खिलेगा वही फलेगा और बढ़ेगा भी। पीएम मोदी की प्रेरणा से देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल स्पर्धा और हर जिले में स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (साई) के सेंटर स्थापित कर खेल की गतिविधियों को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह राज्य के अंदर भी खेल की गतिविधियों को बढ़ाने और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग इसी की कड़ी है।

प्रदेश में अब तक पांच सौ खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खेल से जुड़ी निजी संस्थाओं को भी प्रोत्सहित कर रही है। इसके लिए खेल नीति में संशोधन भी किया गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती से लेकर स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार अब तक पांच सौ से अधिक खिलाड़ियों को सरकार के युवा कल्याण, पुलिस, परिवहन आदि विभागों में सेवायोजित कर उन्हें करियर के प्रति आश्वस्त कर चुकी है। प्रदेश सरकार खेलों को लेकर जो कार्यक्रम चला रही है उससे आने वाले समय मे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी।

ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता यूपी के खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से ओलंपिक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था है। ओलंपिक की टीम स्पर्धा में यह राशि क्रमशः 3, 2 व 1 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह कामनवेल्थ खेल तथा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक विजेता को 75 लाख व कांस्य पदक विजेता को 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये तथा कामनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास करते रहे ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ

इस अवसर पर अपने गुरुदेव और जिनकी स्मृति में यह कबड्डी प्रतियोगिता हुई, का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित रहा। साथ ही वह खेलों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास करते रहे। संबोधन से पूर्व सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

यूपी ने देश को दिए कई प्रमुख कबड्डी खिलाड़ी

सीएम योगी ने कहा कि यूपी ने देश को कई प्रमुख कबड्डी खिलाड़ी दिए। संजीव बालियान, बृजेंद्र, यशपाल, धर्मवीर, योगराज, राहुल चौधरी, नितिन तोमर आदि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने जज्बे से कबड्डी के खेल को नई ऊंचाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी केवल ताकत का खेल नहीं है।

सैलानी अब आसमान से निहार सकेंगे अलौकिक अयोध्या का अद्भुत नजारा

हॉट एयर बलून के जरिये अब 250 फीट की ऊंचाई से निहारिये अयोध्या

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। वाटर मेट्रो बोट के बाद अयोध्या में अब हॉट एयर बैलून की शुरुआत हुई है। सीएम योगी की मंशा पर अयोध्या में शुरू की गई यह सेवा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन गयी है। इस बैलून में बैठने के बाद सैलानी 250 फीट की ऊंचाई से अयोध्या का भव्य नजारा देख सकेंगे। नया घाट हैलीपैड पर बुधवार को इसका शुभारंभ हुआ है। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं की अयोध्या को इस लिहाज से सजाया जाए कि जिससे यहां एक बार पहुंचने वाला श्रद्धालु बार-बार आने का प्रयास करे। इस दिशा में चल रहे कार्यों के तहत अब यहां एयर हॉट बैलून की शुरुआत की गई है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण और पुष्पक एडवेंचर की मदद से शुरू हुए इस कार्य से निश्चित ही पर्यटन की दिशा में अयोध्या को बड़ा मुकाम हासिल होगा।

युवा पर्यटक होंगे आकर्षित

अयोध्या में एडवेन्चर स्पोर्टस के माध्यम से पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने व युवा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हॉट एयर बैलून का शुभारंभ सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मण्डलायुक्त गौरव दयाल व अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार पाण्डेय ने किया। यह अनूठी पहल अयोध्या को एक रोमांचक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने एवं पर्यटकों को सरयू नदी के मनोरम दृश्यों के साथ अयोध्या की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक सुंदरता का अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा।

10 मिनट की राइड, 999 रुपये है किराया

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने बताया कि हॉट एयर बैलून एक एडवेंचर है। इसमें 10 मिनट की राइड होगी। ऊपर से रामलला का मंदिर, कनक भवन व सरयू का अद्भुत नजारा देखने के लिए 999 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ेंगे। इसमें एक साथ चार लोग ही बैठ सकेंगे, जिसमें एक पायलट भी होगा।

आने वाले दिनों में कई प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे: मंडलायुक्त

मण्डलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के तहत अयोध्या में विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हॉट एयर बैलून शुरू कराया गया है। यह हवा के रुख के हिसाब से चलता है। आने वाले दिनों में ऐसे कई प्रोजेक्ट अयोध्या में धरातल पर दिखाई पड़ने लगेंगे।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र विस्तर पर मृत मिला

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के अहिमामऊ स्थित पार्थ अद्यन्त में अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक का शव उसी के विस्तर पर मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि बलिया जिले के सुल्तानपुर गांव निवासी शुभम सिंह (25) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुशांत गोल्फ सिटी के पार्थ अद्यन्त में अपने दोस्त हिमांशु के साथ रहता था। पुलिस के बताया कि मंगलवार की रात खाना खाने के बाद सो गया। बुधवार की सुबह वह विस्तर पर मृत मिला। सुबह जब वह देर तक नही उठा तो दोस्त हिमांशु ने जगाने का प्रयास किया उसे मृत घबरा गया। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

सीएम योगी के नेतृत्व में डिजिटल यूपी का सपना हो रहा साकार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए भारतनेट परियोजना को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से योगी सरकार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़कर उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बना रही है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से प्रदेश में 46,729 ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं।

बता दें कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत देश के सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल अक्टूबर के अंत तक भारत नेट के पहले और दूसरे चरण के तहत लगभग 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इस परियोजना में जहां बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वहीं कुछ चुनौतियों का समाधान भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2024 तक कुल 46729 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल/सैटेलाइट लिंक से जोड़ा जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र में 24575, मध्य प्रदेश में 17850, गुजरात के 14316, आंध्र प्रदेश के 12955 और पंजाब के 12668 ग्राम पंचायत भारत नेट परियोजना से आच्छादित हो चुकी हैं।

लंबित बिजली कनेक्शनों को जल्द जोड़ने का निर्देश

4G सैचुरेशन परियोजना की सफलता के लिए बिजली कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में कुल 132 स्थलों में से 90 स्थलों पर भूमि अधिग्रहण हुआ। इसमें से 39 जगहों पर बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में 42 स्थलों में से 21 पर कनेक्शन दिए गए हैं। यूपी के 22 स्थलों को ₹टेक्निकली नॉट फीज़िबल₹ (TNF) के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 20 घने जंगल क्षेत्रों में स्थित हैं। योगी सरकार ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया है कि लंबित कनेक्शनों को शीघ्रता से जोड़ा जाए और तकनीकी बाधाओं के लिए वैकल्पिक समाधान निकाले जाएं। दिसंबर 2024 तक 8,568 नए एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य है।

योगी सरकार ने समस्याओं के जल्द समाधान के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल यूपी का सपना साकार करने के लिए विभिन्न विभागों को समन्वय बढ़ाने और परियोजना से जुड़े मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ने ग्राम विकास अधिकारियों-पंचायत सचिवों को भारतनेट उपकरणों की देखरेख और उपयोगिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी (संरक्षक) की नियुक्ति होगी। इसके अलावा फाइबर केबल को जहां ₹हर घर जल योजना,₹ सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्यों के कारण क्षति पहुंची है, वहां इन्हें पुनः स्थापित करने का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। वन विभाग को लंबित भूमि आवंटन पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही ऊर्जा विभाग को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करने और कठिन स्थलों के लिए समाधान तलाशने का निर्देश दिया गया है। भारतनेट परियोजना देश के दूरदराज व ग्रामीण इलाकों में न केवल हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान कर रही है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और आर्थिक विकास को गति देने का महत्वपूर्ण साधन भी बन रही है। इस परियोजना के पूरा होने से गांवों के लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

साइबर ठगों ने साढ़े चार लाख रुपए खाते से उड़ाए, मुकदमा दर्ज

लखनऊ। लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक्सिस बैंक के खाता धारक के खाते से साइबर ठगों ने साढ़े चार लाख रुपए उड़ा लिए,पीड़ित ने साइबर सेल में सूचना देने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

अखिलेश गोयल फ्लैट संख्या 410 जे-601, सिलेब्रिटी ग्रींस सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में रहते हैं।

बीते 26अगस्त को इनके खाता संख्या 916010026995930 एक्सिस बैंक , सुशांत गोल्फ सिटी ब्रांच से रु 450,000 निकल गए, उन्होंने साइबर सेल को सूचना देने के बाद, सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।

हेरिटेज वॉक के दौरान प्रशिक्षित गाइड सुनाएंगे महाकुम्भ के इतिहास तथा महात्मय की सुनायेंगें कहानियां

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने महाकुंभ-2025 मेले के दौरान प्रयागराज में हेरिटेज वॉक आयोजित और संचालित करने के लिए दो एमओयू साइन किए हैं। यूपीएसटीडीसी ने 'रूबरू वॉक्स' और 'एनरूट इंडियन हेरिटेज' के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। गौरतलब है कि, यूपीएसटीडीसी ने हाल ही में 'गंगा जमुनी फाउंडेशन' के साथ भी एक एमओयू साइन किया था। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इन समझौतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये साझेदारियां प्रयागराज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने और आगंतुकों को संगम नगरी की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का गहन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'एमओयू की शर्तों के तहत, रूबरू वॉक्स और एनरूट इंडियन हेरिटेज, प्रयागराज के प्रमुख स्थलों जैसे- संगम, इलाहाबाद किला, अक्षयवट और आनंद भवन आदि पर आधारित गहन शोध और योजनाबद्ध टूर डिजाइन करेगा। हेरिटेज वॉक प्रशिक्षित और बहुभाषी गाइडों द्वारा सटीक व रोचक विवरणों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका मकसद प्रतिभागियों को आकर्षक और ज्ञानवर्धक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इन वॉक्स को यूपी पर्यटन द्वारा पर्यावरण और भीड़ प्रबंधन के तय मानकों के अनुरूप पूरा किया जाएगा, ताकि पर्यटकों के लिए यह अनुभव सुरक्षित और यादगार हो।

जयवीर सिंह ने बताया कि रुबरू वॉक्स और एनरूट इंडियन हेरिटेज, प्रयागराज में होने वाले वॉक्स के संचालन का प्रबंधन करेगा, जिसमें बुकिंग, टिकटिंग और शेड्यूलिंग आदि शामिल हैं। महाकुंभ-2025 में यूपीएसटीडीसी की ओर से केंद्र आदि भी स्थापित किए जाएंगे, जो पर्यटकों को संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराएगा। यूपीएसटीडीसी इस पहल के जरिए आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने, तय मार्ग, सुरक्षा-व्यवस्था तथा भीड़ प्रबंधन जैसी सहायता उपलब्ध कराने के साथ विरासत स्थलों तक आगंतुकों की बेरोकटोक पहुंच सुनिश्चित करेगा। यूपीएसटीडीसी और रूबरू वॉक्स इस प्रयास को 'गंगा जमुनी वेबसाइट' से जोड़ेंगे, जो वॉक में शामिल प्रतिभागियों की पहुंच और सुविधा को सुगम बनाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'हेरिटेज वॉक के लिए ये साझेदारियां अहम हैं। यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित और प्रचारित करने के प्रति यूपीएसटीडीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। महाकुंभ-2025 जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने के लिए यूपीएसटीडीसी का प्रयास सराहनीय है।

ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट पर किया जा सकेगा

लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति एस0 पी0 तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आनलाइन आवेदन दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे आरम्भ होगा जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेगा। ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट पर किया जायेगा। तिवारी ने बताया कि हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा दिसम्बर, 2024 के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा ली जाएगी। प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिल्ली में जनवरी, 2025 के प्रथम सप्ताह में सम्भावित है। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

पहले जांच होगी फिर दर्ज होगा मुकदमा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोसाईगंज। थाना क्षेत्र के रानी खेडा गांव के मिले युवक के शव के पोस्टमार्टम के दौरान मौत की पुष्टि स्पष्ट न होने पर विसरा प्रजर्व किया गया। पीड़ति पिता की तहरीर पर पुलिस जांच का हवाला देते हुए बगैर जांच के मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़ति का आरोप है कि पुलिस जान बूझ कर आरोपियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करना नही चाहती है।

जानकारी के मुताबिक अकोहरी थाना मौराव जनपद उन्नाव निवासी अनीस (25) का शव उंसके मामा के घरके पास पाया गया। मृतक के पिता शिवप्रताप का आरोप है कि उनका बेटा 2 नवम्बर को पेशी के लिए घर से लखनऊ आया था। वह पेशी ने बाद अपने मामा के घर सलौली आ गया। पिता का आरोप है कि सलौली निवासी मन्नू सिंह, सहदेव सिंह व गुरु प्रसाद राम ने उसे बुलाकर ले गये उंसके बाद हत्या कर शव मृतक के मामा के घर के पास छोड़ कर भाग गये । पीड़ति को जब घटना की जानकारी हुई तो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिये तहरीर दी। पीड़ति का आरोप हैं कि पुलिस विपक्षियों से मिलकर केस दर्ज करना नही चाहती। इस संबंध में गोसाईंगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मामले की मृतक नशे का आदि था उसके शरीर पर चोट के नही निशान नही थे। विसरा प्रजर्व किया गया है। मृतक के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

शहर में रोजाना चोर एक के बाद बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को दे रहे अंजाम

गोसाईगंज। लखनऊ शहर में रोजाना चोर एक के बाद बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद फरार हो जा रहे हैं । पुलिस सभी मुकदमों में केस दर्ज तक ही सीमित हो जाती हैं। सुशांत गोल्फ सिटी में चोर एक बंद घर को निशाना बनाते हुए हजारों रूपये की नकदी सहित जेवरात चोरी कर ले गए। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के कुल्ली खेड़ा में रहने वाले रमा शंकर पत्नी पुष्पा देवी और बच्चों के साथ रहते है। पुष्पा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती मंगलवार सुबह उनके दोनों बच्चे स्कूल गए थे,इसके बाद वह घर में ताला बंद कर पति के साथ चारबाग चली गई थी। शाम को घर वापस लौटने पर देखा कि कमरों व अलमारी के ताला टूटे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। उनका कहना है कि चोर अलमारी में कान का झुमका,कान का सुईधागा, दो अंगूठी और एक जोड़ी पायल सहित चार गुल्लक फोड़ के लगभग 5-6 हजार की नगदी उठा ले गए हैं।

अडानी को जांच से बचाने का मोदी सरकार का निराशोन्मत्त प्रयास

कई मायनों में, अडानी का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे शक्तिशाली निगमों और राजनीतिक अभिजात वर्ग के हित एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वे लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रियाओं को विकृत कर रहे हैं, जिनकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जब सरकार गंभीर अपराधों के लिए जांच के दायरे में आई किसी कंपनी के पीछे खड़ी होती है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद अडानी समूह और भारत सरकार द्वारा किये गये बचाव ने भारत में कॉरपोरेट हितों और राजनीतिक शक्ति के बीच परस्पर सम्बंधों के बारे में गंभीर सवाल खड़े किये हैं। जहां एक ओर अमेरिकी जांच ने भ्रष्टाचार सहित गंभीर वित्तीय अपराधों को उजागर किया,वहीं अडानी समूह और भारत सरकार दोनों ने कंपनी का बचाव करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा पेश किया और कहा कि आरोपों को केवल तकनीकी रूप से तैयार किया गया है और कम्पनी का नेतृत्व किसी भी कदाचार में शामिल नहीं है। लेकिन बचाव को मोदी सरकार की ओर से कॉरपोरेट हितों को बचाने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में ही देखा जा सकता है।

अमेरिकी आरोप, जो संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों, स्टॉक मूल्य हेरफेर और अपतटीय संस्थाओं से संबंधों की ओर इशारा करते हैं, न केवल कंपनी के संचालन के लिए बल्कि भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके व्यापक प्रभाव के रूप में एक गंभीर खतरा पेश करते हैं। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने अडानी समूह के लेन-देन में गहराई से जांच की है, जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और घरेलू निवेश विश्वास दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। स्थिति की गंभीरता के बावजूद, अडानी समूह और भारत सरकार की प्रतिक्रिया दृढ़ रही है। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने कहा है कि उसके खिलाफ आरोप निराधार हैं, उन्हें गलतफहमी या सबसे खराब स्थिति में, अनुपालन में तकनीकी त्रुटियों के अलावा कुछ नहीं बताया जा सकता। भारत सरकार की ओर से अडानी समूह के बचाव को मजबूत राजनीतिक समर्थन मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि यह निजी संस्थाओं से जुड़ा एक विशुद्ध रूप से कानूनी मामला है, और इसलिए, सरकार से चल रही कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, इस बयानबाजी ने अंतर्निहित प्रेरणाओं के बारे में संदेह को कम करने में बहुत कम मदद की है। मामले को वित्तीय कदाचार के गंभीर मामले के बजाय कानूनी तकनीकी मुद्दों के रूप में पेश करके, अडानी समूह और भारत सरकार दोनों ही रणनीतिक रूप से आरोपों की मूल प्रकृति से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से एक समान रही है, भारत में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और यहां तक कि मीडिया आउटलेट्स ने अडानी समूह के पक्ष में दलीलें दीं तथा इसे वित्तीय घोटाले में उलझी कंपनी के बजाय विदेशी हस्तक्षेप का शिकार बताया। इस बचाव के व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह इस बात पर सवाल उठाता है कि भारत में कॉर्पोरेट प्रभाव किस हद तक सरकारी कार्रवाई से जुड़ा है।

ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रसद में अपने विशाल व्यावसायिक हितों के साथ अडानी समूह भारत की सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में से एक है। इसका उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले दशक में अडानी समूह की धूमकेतु की तरह वृद्धि को अक्सर देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की इसकी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, समूह का बचाव केवल एक कॉर्पोरेट मुद्दा नहीं है - इसे राष्ट्रीय हित का मामला बना दिया गया है।

अगर भ्रष्टाचार के इन आरोपों को दबा दिया जाता है या महज तकनीकी बातों के तौर पर खारिज कर दिया जाता है, तो इससे पारदर्शिता और नैतिक व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में विश्वास कम होने का जोखिम है। अडानी समूह के राजनीतिक हस्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध अच्छी तरह से उजागर हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन संबंधों ने समूह को नियामक जांच की पूरी सीमा से बचाने में मदद की है। इसलिए, समूह का बचाव करने में सरकार की भूमिका ने राजनीतिक अभिजात वर्ग की संभावित मिलीभगत के बारे में चिंता जताई है, जो जवाबदेही पर कॉर्पोरेट सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। अडानी समूह और भारत सरकार दोनों द्वारा निर्मित कथा एक निर्दोष पक्ष के रूप में सावधानीपूर्वक तैयार किये गये चित्रण पर टिकी हुई है, इस आरोप के साथ कि इसे विदेशी शक्तियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। यह बयानबाजी एक व्यापक राष्ट्रवादी कथा की प्रतिध्वनि है जो घरेलू निगमों, विशेष रूप से सरकार के साथ निकटता रखने वालों को अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के शिकार के रूप में पेश करती है।

एक नए राजनैतिक नक्षत्र का उभार

वायनाड की तबाही अक्षम्य राजनीतिक अपराध का परिणामआरक्षण में उप-कोटा की अनुमति देने वाले फैसले में छिपा संभावित राजनीतिक मोड़

अरविन्द मोहन

हेमंत की सफलता दो को छोड़कर सारे आदिवासी ठिकानों से अपने अर्थात झामुमो और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जिताना नहीं है। उसे इनसे या अधिकांश आदिवासी वोट पाने भर से ठीक से समझा ही नहीं जा सकता। सारी रिजर्व सीटों पर तो भाजपा पिछली बार भी हारी थी। हेमंत का असली बड़ा काम है अलग-अलग कबीलों में अब तक बंटे रहे झारखंड के आदिवासी समाज को एकजुट करना। झारखंड के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री चुन लिए जाने के बाद जब हेमंत सोरेन जब दिल्ली आकर अपने शपथ ग्रहण समारोह का न्यौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को देने आए तो कई लोगों को हैरानी हुई क्योंकि उनकी पिछली पारी में इसी जोड़ी ने उनका राज करना मुश्किल कर दिया था और आखिर में लंबी जेल भी काटने को मजबूर किया था। चुनावी लड़ाई में भी चंपई सोरेन और सीता सोरेन जैसे करीबी लोगों को तोड़कर भाजपा ने अपनी राजनैतिक लड़ाई को काफी हद तक सोरेन परिवार के खिलाफ निजी खुंदक जैसा बना लिया था। जो लोग हेमंत सोरेन और झारखंड के आम आदिवासियों का स्वभाव जानते थे उनके लिए यह न्यौता न तो महज औपचारिकता थी ना ही भाजपा के जले पर नामक छिड़कने की कोशिश। न ही इसमें यह जताने का भाव था कि आपने जितना परेशान किया मुझे आदिवासियों और झारखण्डियों का उतना ही पक्का समर्थन मिला। बताना न होगा कि मोदीजी और शाह की अनुपस्थिति के बिना भी हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड था और उन्होंने चुनावी वायदों को पूरा करने का भरोसा दिया।

हेमंत ने इस अवसर पर ही नहीं अपनी सरकार को गिराने की भाजपाई कोशिश के पूरे पांच साल के दौर में बहुत ही मैच्योर पॉलिटीशियन होने का प्रमाण दिया, जो उनके पिता शिबू सोरेन अर्थात गुरुजी समेत कोई आदिवासी नेता नहीं देता था। आम स्वभाव में अन्याय का तगड़ा प्रतिरोध करने वाला आदिवासी अक्सर ऐसी स्थितियों में काफी उग्र प्रतिक्रिया देता रहा है जबकि उसके नेता लोभ और दबाव में टूट जाते रहे हैं। यह बात देश भर पर लागू होती है लेकिन झारखंड पर खास तौर से। वहां नेता बार-बार 'बाइक' हैं लेकिन जनता का बगावती तेवर मद्धिम नहीं पड़ा है। हेमंत ने इसी स्वभाव को पहचान कर उसे अपनी लड़ाई का मुख्य हथियार बनाया। उन्होंने झारखंड और आदिवासियों से भेदभाव का सवाल केन्द्रीय रखा और अपना दावा कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और जब जेल जाने की स्थिति बनी तो सीधी टकराहट (जैसा दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल ने दिखाया) या अपने परिवार के किसी को कुर्सी सौंपने की जगह कोलहान टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन को गद्दी सौंप दी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गद्दी वापस ली तो भाजपा ने उसे भी मुद्दा बनाकर और कुछ लोभ देकर चंपई को अपने पक्ष में किया। माना जाता है कि अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र में आदित्यपुर और गमरिया जैसे जमशेदपुर के शहरी हिस्से न होते तो उनको भी आदिवासी नकार चुके होते।

चंपई हों या सीता सोरेन उनका व्यवहार पहले कांग्रेस या भाजपा या कहें सत्ता के प्रलोभनों और दबाव में टूटे अन्य आदिवासी नेताओं जैसा ही रहा। जबकि हेमंत ने तब भी दो पावर सेंटर न बनने देने की जबरदस्त व्यावहारिक सोच दिखाते हुए(कहा जाता है कि यह सुझाव सोनिया गांधी का था) मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले ली। और देखा कि उन्होंने कितनी मुश्किल लड़ाई को किस आसानी से जीत लिया। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा सरमा जैसों की महीनों की कवायद और भाजपा का सारा संसाधन धरा रह गया। घुसपैठ का मुद्दा बनाने के लिए भाजपा ने(जिसके असली सूत्रधार मोदी-शाह ही रहे) आखिरी दिन तक छापा, गिरफ्तारी, कथित मनी-ट्रेल बनाने जैसी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ काम न आया। बल्कि उसे अब तक आराम से मिलने वाला ओबीसी वोट भी इस बार पहले से कम हुआ और उसे सिर्फ शहरी और अगड़ा वोटरों का सहारा रह गया। आदिवासी वोट तोड़ने की सारी कवायद फेल हो गई और अंतिम समय अपनी पार्टी का विलय करके भाजपा अध्यक्ष बने बाबूलाल मारांडी को भूमिहार वोट के सहारे जीतना पड़ा। इसके लिए नाराज पूर्व सांसद रवींद्र राय को मनाना और बागी नित्यानंद राय को बैठाने में जोर लगाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि भाजपा की तरफ से सिर्फ बाबूलाल मारांडी और चंपई सोरेन ही जीत पाए थे।

हेमंत की सफलता दो को छोड़कर सारे आदिवासी ठिकानों से अपने अर्थात झामुमो और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जिताना नहीं है। उसे इनसे या अधिकांश आदिवासी वोट पाने भर से ठीक से समझा ही नहीं जा सकता। सारी रिजर्व सीटों पर तो भाजपा पिछली बार भी हारी थी। हेमंत का असली बड़ा काम है अलग-अलग कबीलों में अब तक बंटे रहे झारखंड के आदिवासी समाज को एकजुट करना। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिबू सोरेन उरांव प्रभुत्व के तमाड़ इलाके में जाकर अनजान पीटर से हार गए थे। आदिवासियों की नई एकजुटता तो भाजपा द्वारा पहला गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री(रघुवर दास) बनाने से ही शुरू हुई थी लेकिन उसे एक अंजाम तक लाना आसान न था। हेमंत ने यह काम किया और आज वे शिबू सोरेन समेत किसी भी आदिवासी नेता की तुलना में बड़ा और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इसलिए अब उनकी जवाबदेही ज्यादा बड़ी है-झारखंड के साथ मुल्क भर के आदिवासियों की आवाज बनाना और देश की राजनीति में आदिवासी स्वर को अधिक प्रमुख स्थान दिलाना। हेमंत ने अपना कौशल इंडिया गठबंधन के साथी दलों के दावों और उम्मीदवारों को संभालने में भी दिखाया। यह जरूर है कि राहुल गांधी ने उनको फ्री-हैंड दिया लेकिन झारखंड चुनाव अभियान लगभग पूरी तरह हेमंत के कंधों से ही चला।

अगर कोई श्रेय में दावेदारी कर सकता है तो वह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही हैं जिन्होंने घटक दलों की पंचायत या सरकारी कामकाज भी निपटाने जैसे जिम्मों से मुक्त होकर हेमंत से भी ज्यादा चुनावी सभाएं कीं। वे अच्छा बोलती हैं तथा कार्यकर्ताओं और खास तौर से महिलाओं के बीच अच्छे व्यवहार से असर छोड़ती हैं। बिना किसी राजनैतिक प्रशिक्षण के एक बार में ऐसी भूमिका निभाकर उन्होंने सबको हैरान किया है। भाजपा ने चाहे जिस रणनीति से हेमंत को जेल भेजा हो पर उसने कल्पना न की थी कि इस संकट से कल्पना सोरेन जैसी नेता उभर कर आएंगी। झारखंड के आदिवासियों में औरतों का स्थान आम हिन्दुस्तानी परिवार से ऊंचा है, उनकी आर्थिक कामकाज में भी हिस्सेदारी ज्यादा होती है लेकिन विधायक-सांसद होकर भी आदिवासी महिलाएं पार्टी के नेतृत्व में या राज्य की राजनीति नेतृत्व नहीं करती थीं। कल्पना सोरेन के रूप में इस बार उन्हें एक नया नेता मिला है तो हेमंत सोरेन को बोनस। और हैरानी नहीं कि दो हेमंतों की लड़ाई में हेमंत सोरेन ने इस सहारे से हिमंत बिस्वा सरमा को उनके राजनैतिक कैरियर का सबसे बड़ा झटका दिया है।

अजब-गजब

लड़के ने मछलियों से बना डाली मॉडल जैसी ड्रेस, दिखाया उर्फी जावेद वाला स्वैग

आपने एक्ट्रेस उर्फी जावेद को अक्सर अतरंगी आउटफिट में देखा होगा। वह सोशल मीडिया की वो मशहूर हस्ती हैं, जो कैमरे के सामने ऊटपटांग ड्रेस में भी पोज देने से नहीं हिचकतीं। लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर नेटिजन्स कह रहे है- लगता है मार्केट में उर्फी का बड़ा भाई आ गया है। दरअसल, वायरल वीडियो में एक लड़के ने जिस तरह से मछलियों से बनी पोशाक पहनी है उसे देखकर पब्लिक ने सिर पीट लिया है।

वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान इन्फ्लुएंसर नेनवथ थरुन के रूप में हुई है, जो उर्फी की ही तरह अपने विचित्र फैशन सेंस के लिए मशहूर हैं। वह अक्सर ऊटपटांग कपड़ों, पत्तों से बनी ड्रेस में और मशहूर हस्तियों की नकल करते हुए वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसने पब्लिक को हैरान कर दिया है।

थरुन का जो रील वायरल हुआ है, उसमें उन्हें असली मछलियों से बुनी हुई ड्रेस पहने हुए दिखाया गया है। यही नहीं, वह बड़े स्वैग के साथ मछली से बना पर्स भी पकड़ा हुआ है। वीडियो में आप देखेंगे कि उन्होंने मछलियों से बनी नेकलेस और इयररिंग्स भी कैरी की है। थरुन की ये अतरंगी ड्रेस इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। ये भी देखेंः लड़की ने बीच सड़क लोगों को रोककर पूछा एक सवाल, सुनते ही हंस पड़े

इसे @tik_toker_tharun_nayak नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक 11 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि कमेंट्स की झड़ी लग गई है। एक यूजर ने लिखा, भाई अब मच्छर से बनी ड्रेस पहनकर दिखाओ। दूसरे यूजर का कहना है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। तीसरे यूजर ने कमेंट किया, बच कर भाई कोई पकड़कर तल ने दे।

ब्लॉग

संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ नहीं, महज एक कानूनी ग्रंथ है जो भेदभाव से परे नहीं है!

कमलेश पांडे

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि हमने संविधान के जरिए सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के कई बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है। संविधान निर्माताओं की प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित है। हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी का ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ नहीं! क्योंकि पवित्र ग्रंथ तो वेद-पुराण, बाइबिल, कुरान आदि धार्मिक पुस्तकें हैं, जिनकी पंक्ति में किसी भी कानूनी दस्तावेज को खड़ा करना इन विश्वासों को खंडित करने जैसा है। दुनिया भर के संविधान इन आरोपों से परे नहीं हैं।

लिहाजा, राष्ट्रपति मुर्मू के इस विचार से पवित्र और पवित्रता शब्द के उपयोग पर एक नई बहस छिड़ना लाजिमी है। क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था/वस्तुओं के लिए पवित्र शब्द का उपयोग करना, न तो भाषा सम्मत है, न ही न्यायसंगत! इससे विषयगत भ्रांतियां पैदा होती हैं। सच तो यह है कि भारत का संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक कानूनी ग्रंथ है जो भेदभाव से परे नहीं है, इसलिए इसमें जनहित के नजरिए से व्यापक बदलाव अपेक्षित है! ऐसी मांगे समय-समय पर उठती आई हैं जिसे बहुमत द्वारा दबा दिया जाता है। इसलिए सर्वसम्मति वाले लोकतंत्र की जरूरत यहां ज्यादा है, क्योंकि यह विविधताओं में एकता वाला देश है। यहां के नियम-कानूनों में जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र आदि की बू नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा है!

वहीं, रही बात संविधान के पवित्र ग्रन्थ होने की तो यहां पर यह याद दिलाना जरूरी है कि पवित्र शब्द किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करता है जो किसी देवता की सेवा या पूजा के लिए समर्पित या अलग रखी गई हो; जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए पवित्र शब्द से इसकी उपमा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी पवित्रता आध्यात्मिक सम्मान या भक्ति के योग्य मानी जाती है; या विश्वासियों के बीच भय या श्रद्धा को प्रेरित करती है। अमूमन, संपत्ति को वस्तुओं (एक ₹पवित्र कलाकृति₹ जिसे सम्मानित और आशीर्वाद दिया जाता है), या स्थानों (₹पवित्र भूमि₹) के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इससे मतभिन्नता पैदा होती है।

आधुनिक लोकतंत्र के जन्मदाता फ्रांस के समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने पवित्र और अपवित्र के बीच के द्वंद्व को धर्मविशेष की केंद्रीय विशेषता माना है। क्योंकि ₹धर्म पवित्र चीजों से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है, यानी अलग रखी गई और निषिद्ध चीजें।₹ दुर्खीम के सिद्धांत में, पवित्र समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से एकता, जो पवित्र समूह प्रतीकों में सन्निहित है, या मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करने के लिए टीम वर्क का उपयोग करती है। दूसरी ओर, अपवित्र में सांसारिक व्यक्तिगत चिंताएँ शामिल हैं।

यह भी कड़वा सच है कि हमारा संविधान मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र आदि व्यवस्थागत पुस्तकों का एक महज विस्तार भर है, जिसमें आधुनातन विचार शामिल किए गए हैं। यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है! आप मानें या न मानें, लेकिन हमारा संविधान भी बहुमत पर आधारित एक सत्तागत प्रवृत्ति का द्योतक है जो सत्ता की प्रकृति के बदलते ही बदल जाएगी। भले ही इसमें सभी धर्मों/मतों की जरूरतें शामिल हैं, फिर भी इस्लाम मतावलंबियों द्वारा जिस तरह से सरिया कानून लागू करने की मांग उठ रही है, वह तो महज एक उदाहरण है। इसी तरह सनातन मतावलंबियों में भी वैदिक कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है, जो हिन्दू धर्म/सनातन मान्यताओं की परम्पराओं पर आधारित हों। वहीं, आदिवासी समुदाय की ओर से भी ऐसी मांगें उठी हैं। ऐसी मांगे भविष्य में सभी धर्मावलंबियों के द्वारा की जा सकती है। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत के संविधान की रचना पश्चिमी देशों की मान्यताओं के अनुरूप की गई है, जो भारत के पुरातन संस्कारों से ज्यादा मेल नहीं खाती है। इसलिए इस पर एक स्वस्थ परिचर्चा अपेक्षित है।

वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मत से सहमत हुआ जा सकता है कि संविधान हमारी हर जरूरत और अपेक्षा पर खरा उतरा है, जो हमारा मार्गदर्शक है। देश में जब इमरजेंसी लगी तब भी संविधान ने लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना किया और वह हर अपेक्षा पर खरा उतरा। परिवर्तन के दौर में संविधान गाइडिंग लाइट की तरह है जो रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि, विभिन्न मुद्दों पर संविधान सभा में लंबी बहस हुई थी और गम्भीर चर्चाएं हुई थी। लिहाजा, संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उचित समय पर निर्णय लेते हुए इसकी व्याख्या की जा सकती है।

उनकी इस बात में भी दम है कि भारत की आकांक्षाएं समय के साथ नई ऊंचाई पर जाएंगी। इसलिए हमारा संविधान वर्तमान भारत और भविष्य का मार्गदर्शक है। इसने सभी चुनौतियों का समाधान करने का काम किया है और रास्ता दिखाया है। हालांकि, भारत के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ और गरिमामयी जिंदगी मिले, इसके लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय अहम है। इसके लिए कुछ बदलाव अपेक्षित हैं। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए ठीक ही कहा कि भारत को ईमानदार लोगों के समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट की यही भावना भारत के संविधान को आने वाले कई सदियों को जीवंत बनाए रखेगी।

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी ठीक ही कहा है कि भारत ने विभाजन की भयावहता, अशिक्षा, गरीबी और कमजोर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर एक आत्मनिर्भर, जीवंत लोकतंत्र और भू-राजनीतिक नेतृत्व कर्ता बनने तक का परिवर्तन कारी सफर तय किया है। इस बदलाव का श्रेय संविधान को है। इसलिए संविधान एक दस्तावेज भर नहीं है बल्कि यह जीने का तरीका बन चुका है और संविधान ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। देश ने जो परिवर्तनकारी सफर तय किया है, उस यात्रा के पीछे भारत का संविधान है, जिसने यह परिवर्तन लाने में मदद की है। यह आज जीवन जीने का एक तरीका है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, जिन लोगों की चिंता हमारा संविधान नहीं करता और बेतरतीब दलीलें संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दी जाती हैं, उनकी चिंता भी इसमें शामिल करना होगा और संविधान संशोधन करने होंगे, अन्यथा इसके सर्वस्वीकार्यता पर सवाल खड़े होंगे ही। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो लोगों को मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य का दायित्व देता है। वहीं सरकार को सुशासन के लिए नीतिनिर्देशक सिद्धांत भी देता है। यहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के काम में विभाजन है। फिर भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एससी, एसटी और ओबीसी के सामने खड़ी दीवार को और मजबूत कर रही है। और इसी क्रम में जब यह स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार में इस दीवार को कमजोर करने का काम जिस मजबूती से होना चाहिए, वह नहीं हुआ, तो संविधान व सरकार की सोच और सफलता दोनों पर सवाल उठना लाजिमी है। बहरहाल, संविधान की संस्कृत भाषा के संस्करण का लोकार्पण प्रशंसनीय है, लेकिन संस्कृत के सर्वग्राही संस्कारों से इसे कब समृद्ध किया जाएगा, यह सवाल यक्ष प्रश्न बनकर समुपस्थित है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जैसे इसके विचार व्यक्तिपरक होने चाहिए, दुर्भावना प्रेरित नहीं! इसलिए इसमें समसामयिक वाद-विवाद और संशोधन की गुंजाइश को सर्वसम्मत बनाया जाना चाहिए, बहुमत आधारित नहीं! वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः तभी सम्भव है, जब कानूनी भेदभाव तार्किक हो, परम्परागत नहीं!

संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन! मिले कारतूस, एनआईए कर सकती है जांच

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। संभल हिंसा में घटना स्थल से पाकिस्तानी कारतूस मिला है। यहां से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (POF) की गोलियां बरामद की गई हैं। इस मामले गंभीरता और पाकिस्तानी कनेक्शन होने की संभावना को देखते हुए एसपी ने कहा है कि NIA की तरफ से इसकी जांच की जा सकती है। संभल में जांच के दौरान हिंसा ग्रस्त इलाकों में नाली और सड़क किनारे POF लिखे हुए कारतूस मिले।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हिंसा के दौरान ये कारतूस पुलिस पर चलाए गए थे। पुलिस ने हिंसा में यहां से तमंचे और करीब 50

कारतूस अभी तक बरामद किए हैं। जांच में पुलिस ने मौके से विदेशी हथियार के खोखे भी बरामद किए हैं। खोके में मेड इन यूएसए लिखा हुआ पाया गया है। पुलिस इस मामले में अब जांच करेगी कि क्या फायरिंग के समय दंगाइयों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था, उन्हें ये हथियार कहां से मिले? इसका सोर्स क्या था? संभल तक ये खोके और हथियार कैसे पहुंचे?

पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

संभल में हिंसा के 10 दिन बाद भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस को यहां से 3 बुलेट सेल मिले। मस्जिद के सामने वाली सड़क के पास तीनों ही नाली से पाए गए हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन्हें जानबूझकर नाली में फेंक दिया गया है या फिर हिंसा के दौरान ये गलती से गिर गए? क्या दंगाइयों ने सबूत मिटाने के लिए नालियों में डाला गया? पुलिस कई पहलुओं के जरिए इस पर जांच कर रही है।

संभल मामले में फिलहाल, न्यायिक जांच चल रही है। इसके लिए तीन सदस्यी टीम का गठन किया गया है। जांच की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट के सामने हुए 10 पुलिस कर्मियों के बयान हुए हैं, इनमें वहां के सीओ भी शामिल हैं। राज्यपाल की तरफ से न्यायिक जांच के लिए टीम बनाई गई है। मामले में जिला प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हुए हैं जो मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। एक जांच राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई जुडिशल कमीशन को दी गयी है। न्यायिक जांच की टीम में पूर्व आईपीएस, पूर्व आईएस और अध्यक्ष के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कर सकते हैं मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन

प्रयागराज। प्रयागराज विश्व से सबसे बड़े मानवीय समागम और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुम्भ 2025 का साक्षी बनने जा रहा है। दुनिया के कोने-कोने से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के महाकुम्भ में आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री महाकुम्भ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। उनके विजन और मार्गदर्शन के मुताबिक मेला प्राधिकरण और अन्य सभी विभाग महाकुम्भ की तैयारियों में पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्यरत हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुम्भ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रयागराज आ रहे हैं। इस अवसर पर वो मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन व अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्टस का निरीक्षण भी करेंगे।

महाकुंभ के लिए हुई पैसों की बरसात, केंद्र और राज्य ने दिया फंड

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जनवरी महीने में शुरू हो रहे इस आयोजन से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोला है। प्रयागराज में शुरू हो रहे सबसे बड़े सांस्कृतिक व आध्यात्मिक समागम महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत। सरकार ने इसकी पहली किस्त 1050 करोड़ भी जारी कर दी है।

महाकुंभ का आयोजन और दिव्य, भव्य व डिजिटल तरीके से करने में सहायता मिलेगी। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है,

जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित किया जाता है। विशेष सहायता अनुदान के लिए प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था।

राज्य सरकार ने दिया कितना फंड?

उत्तर प्रदेश सरकार 5435।68 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्च कर रही है। यह राशि 421 परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है। प्रदेश सरकार अब तक 3461।99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर चुकी है।

यूपी के प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेला क्षेत्र में परेड ग्राउंड पर 100 बेड का मुख्य अस्पताल लगभग तैयार है। बन रहे 100 बेड के अस्पताल में मेल, फीमेल और चिल्ड्रन वार्ड अलग-अलग बनाए जा रहे हैं। यहां डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर्स रूम भी होंगे। हर 12 साल पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है।

चार तीर्थ स्थलों पर किया जाता है आयोजित

महाकुंभ का आयोजन चार तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रयागराज के संगम के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है।

संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में करवाई 'नेताजी' की मुलाकात... अब नप गए जेलर, हुआ ये एक्शन

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हिंसा हुई थी, जिसमें शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद आरोपियों से मिलने के लिए सोमवार को समादवादी पार्टी के कुछ नेता जेल पहुंचे थे। उन्होंने सभी आरोपियों से मुलाकात की। इस मुलाकात को अवैध बताया गया और अब इसको लेकर कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर डीजी जेल ने मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को सस्पेंड कर दिया।

संभल हिंसा के आरोपियों को संभल में जिला जेल ने होने की वजह से मुरादाबाद जेल में बंद किया गया है। वहीं पर दो दिसंबर को सपा नेताओं ने उन आरोपियों से मुलाकात की थी। आरोप है कि पूर्व सांसद और विधायकों के साथ कुछ सपा

नेताओं ने बगैर पर्ची लिए ही आरोपियों से मुलाकात की थी। इसके बाद मुलाकात की शिकायत की गई। शिकायत के बाद इस मामले को लेकर शासन के निर्देश पर डीजी जेल ने डीआईजी जेल कुंतल किशोर को मामले की जांच सौंपी थी।

जेल अधीक्षक पर भी कार्रवाई

इसी के चलते मुरादाबाद जिला जेल में सपा नेताओं की मुलाकात के बाद वहां के जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को डीजी जेल पीवी राम शास्त्री ने संस्पेंड कर दिया है। यही नहीं जेलर और डिप्टी जेलर के अलावा शासन से जेल अधीक्षक पीपी सिंह के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई है। जेल अधीक्षक पर भी लापरवाही बरतने का आरोप है।

मुलाकात के बाद किया था पोस्ट

जेल में बंद आरोपियों से मिलने वाले सपा नेताओं में विधायक नवाब जान, चौधरी समरपाल सिंह, पूर्व सांसद एसटी हसन के साथ कई के नाम शामिल हैं। इनके अलावा कुल 15 लोग जेल में आरोपियों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा था, "समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मुरादाबाद जिला कारागार में बंद संभल हिंसा के निर्दोष लोगों से समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उनका दुख-दर्द जाना"

महराजगंज : दूल्हे की एंट्री पर हुई फायरिंग, दुल्हन पक्ष के व्यक्ति को लगी गोली... मचा बवाल

आर्यावर्त संवाददाता

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शादी समारोह में बारातियों द्वारा गोली चलाने की घटना सामने आई है। गोली चलते ही शादी में भगदड़ मच गई। गोलिबारी में एक युवक को गोली लगी है, जिसका नाम राजन तिवारी बताया जा रहा है। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ने जांच शुरू कर दी है।

घुघली थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में बारात आई थी। यहं एक मैरिज हॉल में बारातियों के स्वागत का आयोजन किया गया था। यहीं पर शादी का पूरा कार्यक्रम होना था। कन्या पक्ष बारात के इंतजार में सारी तैयारियों को पूरा कर चुका था। बारात जयप्रकाश नगर मोहल्ले से मैरिज हॉल में पहुंची। गाजे-बाजे के साथ शादी में परिवार के सभी सदस्य

शामिल हुए।

किसे लगी गोली?

कन्या पक्ष से राजन तिवारी उन लोगों में शामिल थे जो बारातियों का स्वागत कर रहे थे। जैसे ही बारात गेट पर पहुंची, वर पक्ष के लोगों को माला पहनाया गया और उनका स्वागत किया गया। इसी बीच लड़की वालों की तरफ से किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान राजन तिवारी के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। घायल राजन तिवारी को डॉक्टर के पास ले जाया गया।

इधर, घटना की जानकारी पाते ही सदर कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षक मनोज कुमार राय के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने बारातियों से 11 गोलियां भी बरामद की हैं और शादी के बुक कैमरा मैन से शादी की रिकार्डिंग भी अपने कब्जे में ले ली है ताकि आरोपी की पहचान हो सके।

क्या बोले घायल राजन?

घायल व्यक्ति राजन तिवारी ने बताया कि वो पटीदारी यानी खानदान में हो रही शादी में शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि रिश्ते में वो लड़की के बाबा लगते हैं। राजन तिवारी के मुताबिक, 'अभी जैसे ही बारात गेट पर पहुंची थी, किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे पैर में गोली लग गई।' घायल की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

देवर–भाभी को चढ़ा इश्क रोग, जब सताया राज खुलने का डर, कर डाला बड़ा कांड

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में 29 नवंबर को 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अब इस मामले को सुलझा लिया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मासूम के चाचा ने ही की थी। हैरानी की बात तो ये है कि इस हत्याकांड में बच्चे की मां भी खुद शामिल थी। बच्चे ने मां को चाचा के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। कहीं राज न खुल जाए, इस डर से दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला।

मामला पिनाहट के नया पुरा मोहल्ले का है। यहां रहने वाले आठ वर्षीय रौनक की हत्या उसी के चाचा ने कर दी। बच्चे की मां के साथ अवैध संबंधों के खुलासे के डर से रौनक को

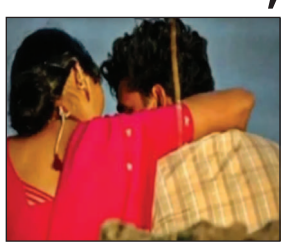

चाचा ने मोगरी से सिर पर प्रहार करके मार डाला। पुलिस ने मृतक रौनक के चाचा और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद चाचा ने रौनक के शव को छत पर रखी करब में छिपा दिया था।

जानकारी के मुताबिक, नया पुरा मोहल्ले से 29 नवंबर की शाम को करन सिंह का आठ वर्षीय बेटा रौनक घर के सामने से लापता हो गया था। सोमवार सुबह रौनक का शव करन सिंह के घर के पीछे गली में बोरे में मिला था। छानबीन के दौरान पुलिस को रौनक के चाचा भानु सिंह की छत पर खून के निशान मिले थे। भानु के घर में सीढ़ी पर खून के निशान से पुलिस को उस पर शक था। भानु सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया।

चाचा भानु ने बताया कि बड़े भाई सूरत में कारखाने में काम करते हैं। यहां पर भाभी यशोदा दोनों बेटों के साथ रहती हैं। उसके भाभी यशोदा के साथ चार वर्ष से अवैध संबंध थे। भाई कभी कबार ही घर आते हैं। इन दिनों भैया घर पर आए हुए थे। वह शुक्रवार शाम बाजार गए हुए थे। तब रौनक ने उसे और अपनी मां को संबंध बनाते देख लिया। दोनों को लगा कि रौनक पिता को बता देगा। जिससे उन्हें रौनक की हत्या करनी पड़ी।

अपहरण का मचाया हल्ला

आरोपी बोला- यशोदा ने बेटे को टॉफी खरीदने के लिए बाहर भेज दिया। वह रौनक को बहाने से अपने कमरे पर लेकर गया। वहां उसके सिर पर मोगरी से प्रहार करके हत्या कर डाली। शव को सीढ़ियों पर रखे ड्रम के ऊपर रखकर बोरा डाल दिया। सीढ़ी पर बहे खून को साफ कर दिया। इस दौरान यशोदा दरवाजे पर खड़ी होकर नजर रखे रही कि कोई बाहर अंदर न आए। भानु ने शव को अंधेरा होने पर बोरे में बंद करके मंझले भाई रवि के घर की छत पर रखी करब के पीछे छिपा दिया था। इसके आधे घंटे बाद यशोदा ने गांव में बेटे के अपहरण का हल्ला मचा दिया।

दोनों करते रहे नाटक

मुकदमा दर्ज कराने के बाद चाचा भानु रौनक को तलाशने का नाटक करता रहा। शव कई दिन पुराना होने के चलते उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती। इसलिए उसे ठिकाने लगाने के लिए यशोदा सोमवार सुबह मोबाइल को चार्जिंग में लगाने के बहाने कमरे से निकल आई। दोनों ने शव को करब से निकालकर बोरे को रस्सी से बांधा। वह गली में चला गया, यशोदा ने छत से रस्सी की मदद से बोरे को गली में नीचे उतारा था। फिर उसे ठिकाने लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।

एकतरफा आशिकी में बन गया कातिल... जिससे करता था बेपनाह मोहब्बत, उसके मंगेतर को सुलाया मौत की नींद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सनकी युवक ने एक स्कूल टीचर को मौत के घाट उतार डाला। युवक ने पहले शिक्षक का अपहरण किया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी। उसने टीचर को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उसने शिक्षक को चरथावल क्षेत्र के गांव रसूलपुर के जंगल में नाले में फेंक दिया, जहां से उनका शव बरामद किया गया। युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पूरा घटना को अंजाम दिया।

दरअसल मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव अटाली के रहने वाले योगेश कुमार बरला इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उनकी एक लड़की से सगाई तय हुई थी, जिससे वह फोन पर बात किया करते थे। उनकी 8 दिसंबर को सगाई

होने वाली थी। इसके लिए वह अपनी मंगेतर के साथ शॉपिंग भी कर रहे थे लेकिन ये बात शिक्षक की मंगेतर के एक तरफा प्यार में पागल आशिक को अच्छी नहीं लगी और उसने साजिश रचकर शिक्षक को मार डाला।

मंगेतर से एकतरफा प्यार

आरोपी युवक के खिलाफ मृतक शिक्षक की बहन सिमलेश ने सोमवार को अपने भाई के अपहरण का केस दर्ज कराया था। उन्होंने परमजीत और अमित के खिलाफ ये केस दर्ज कराया था। साथ ही बताया कि दोनों ने पहले भी शिक्षक को धमकी दी थी। अमित ही शिक्षक की मंगेतर से एकतरफा प्यार करता था। दोनों की सगाई तय हो जाने के बाद उसने अपने दोस्त परमजीत के साथ मिलकर शिक्षक की हत्या की साजिश रची और उन्हें किडनैप कर लिया।

एक को किया गिरफ्तार

इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के दोस्त परमजीत को सैदपुर शनि देव मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई। इसके बाद शिक्षक का शव रसूलपुर के नाले से बरामद किया गया। अमित अभी भी फरार है, लेकिन उसे जल्द ही ढूंढने की बात कही जा रही है। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शिक्षक का कार से अपहरण किया गया था। इसके बाद डंडों से पीट पीटकर उनकी हत्या की गई। मौके से कार, दो डंडे और एक रस्सी भी बरामद की गई है।

भगवान कृष्ण यदुवंशी नहीं, जाट थे? नंदगांव की दीवारों पर लिखी बातों से मचा बवाल

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जाति जाट बताई गई। कुमार साहब सिंह नामक शख्स ने घरों की दीवारों पर श्री कृष्ण को लेकर ऐसी बातें लिखवाईं। इसे लेकर जमकर बवाल मचा। पुलिस ने फिर उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की और दीवारों पर लिखीं उन बातों को मिटवाया।

मामला नंद गांव का है। मंगलवार को जब लोगों की नजर घरों की दीवारों पर लिखी बातों पर गई तो बवाल मच गया। लोग बरसाना थाना पहुंचे। वहां फिर नगर पंचायत की तरफ से FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में एक्शन लिया है।

राधा कृष्ण की लीलाओं का नंदगांव बरसाना का कण-कण भगवान के कुल वंश आदि का प्रमाणिक तमाम पुराण ग्रंथों मैं मिलता है इसके बावजूद कुमार साहब सिंह नाम के व्यक्ति एन दीवारों पर जगह-जगह नंदगांव का इतिहास लिखवाया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को जाट कुल का बताया है।

नंद गांव में रहने वाले सुशील गोस्वामी ने कहा- यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा करके जातीय द्वेष फैलाने की साजिश की गई है। नंदगांव के घरों की दीवारों पर नंदगांव का इतिहास शीर्षक से जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की जाति जाट लिखवा दिया गया। ऐसा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को शख्स ने ठेस पहुंचाया है।

पुलिस ने लिया एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने फिर इस पर एक्शन लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार निरवाल ने बताया- कुमार साहब सिंह नामक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जो विवादित टिप्पणी दीवारों पर लिखी गई थी उसको मिटा दिया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।

नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन

प्रयागराज। नोएडा में किसानों पर लाठी चार्ज के विरोध में बुधवार को प्रयागराज में किसानों से प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि गिरफ्तार 160 किसानों को तत्काल छोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह राकेश टिकैत के आवाहन पर अपने ट्रैक्टर से लखनऊ के लिए कूच करेंगे। संगठन के नेताओं ने कहा कि किसानों के साथ सरकार का यह यह बर्ताव ठीक नहीं है।

भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने बताया कि बुधवार को भी नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के नीचे विशाल धरना चल रहा है। जहां राकेश टिकैत जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उनको टप्पल में रोक लिया और हिरासत में ले लिया। इसका भी किसान लगातार विरोध कर रहे हैं।

अनुज सिह ने बताया कि बुधवार को भी नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के नीचे विशाल धरना चल रहा है। जहां राकेश टिकैत जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उनको तप्पल में रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

घूसखोर अधिकारी! बिजली कनेक्शन के लिए मांगे 60 हजार, 10 हजार लिया एडवांस... फिर ऐसे पकड़ा गया

आर्यावर्त संवाददाता

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा में एंटी करप्शन टीम ने विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को 30 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जेई ने बिजली के कनेक्शन करने के लिए उपभोक्ता से 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ति उपभोक्ता ने रिश्वत के 10 हजार रुपये पहले दे दिए थे। बाद में उसने 30 हजार रुपये दिए। जेई की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत उसने अलीगढ़ एंटी करप्शन टीम को मिली। छापे के दौरान टीम को जेई के आवास से रिश्वत की रकम भी बरामद हुई है।

मामला एटा जिले की अलीगंज थाना क्षेत्र का है। अलीगंज उपखंड विद्युत विभाग में अर्जुन सिंह जेई के पद पर तैनात हैं। उसके खिलाफ अलीगढ़ एंटी करप्शन टीम को रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जूनियर इंजीनियर को 30 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जेई मथुरा

जिले के थाना माटी क्षेत्र के गांव नवीपुर का रहने वाला है।

बिजली कनेक्शन के लिए मांगी 60 हजार की रिश्वत

एंटी करप्शन टीम ने आरोपी जेई के खिलाफ अलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टीम प्रभारी देवेंद्र कुमार के मुताबिक, अलीगंज थाना क्षेत्र के मौहल्ला काजी निवासी आबिद अली ने विद्युत विभाग को 5 किलो वाट के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। उसने जेई अर्जुन से कनेक्शन के लिए कहा टघा। आरोप है कि जेई ने उससे कनेक्शन के लिए 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। आबिद ने 10 हजार रुपये इसके लिए पहले ही दे दिए थे। उसके बाद उसे अगली रकम देनी थी।

रिश्वत लेते पकड़ा जेई

पीड़ित आबिद ने इसकी शिकायत अलीगढ़ एंटी करप्शन टीम से की थी। देवेंद्र कुमार ने बताया कि आबिद द्वारा आरोपी जेई को रिश्वत के 30 हजार रुपये और देने थे। इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को पहले ही दी जा चुकी थी। जब आबिद ने 30 हजार रुपये जेई को दिए तब एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। टीम आरोपी को थाने ले गई। मंगलवार की देर रात आरोपी जेई के खिलाफ अलीगंज थाने में शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एंटी करप्शन की टीम आरोपी जेई को मेरठ ले गई।

लंबे समय तक रहना चाहते हैं हेल्दी, तो आज से ही डाइट में शामिल करें ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स

नेशनल न्यूट्रिशन वीक को मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहत पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए खानपान की हेल्दी आदतों को अपनाना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स शामिल करते हैं तो कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं फिट रहने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए।

हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपनी हेल्थ और खानपान को लेकर जागरूक रहें। सेहतमंद रहने के लिए डाइट में न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाद्-पदार्थों को शामिल करना बेहद जरूरी है।

साल 1975 में नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन (एडीए) द्वारा की गई थी। इस सप्ताह का उद्देश्य संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल के फायदों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए खानपान की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट में अनहेल्दी चीजों को शामिल करते हैं, तो इससे आप कई गंभीर बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में किन पौष्टिक चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है।

सेहतमंद रहने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

पालक

पोषक तत्वों से भरपूर पालक सेहत संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसमें विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन-के, आयरन, कैल्शियम, फाइबर जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो इम्यून सिस्टम तो मजबूत रखता है। यह हड्डियां और पाचन को स्वस्थ रखने में भी मददगार है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पालक को डेली डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।

क्विनोआ

क्विनोआ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। इसमें फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। यह वेट कंट्रोल करने में भी मददगार है। इसके अलावा यह पाचन को भी बढ़ावा देता है। साथ ही रक्त शर्करा के स्तर में भी सुधार करता है।

बादाम

बादाम में हेल्दी फैट्स, फाइबर और विटामिन-ई पाए जाते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में बादाम खाने से स्किन भी ग्लो करती है।

स्वीट पोटेटो

स्वीट पोटेटो विटामिन-ए, विटामिन-सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये आंखों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। स्वीट पोटेटो खाने से इम्युनिटी भी मजबूत होती है, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।

दाल

दाल सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाती हैं। ये प्रोटीन, फाइबर, आयरन और फोलेट का समृद्ध स्रोत होती हैं। दाल हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा है। आप अपनी डाइट में मसूर, दाल, मूंग दाल, अरहर दाल आदि शामिल कर सकते हैं।

ब्रोकली

विटामिन-सी और विटामिन-सी के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ब्रोकली आपकी सेहत के लिए बेहद लाभदायक है। यह सब्जी हड्डियों के स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है।

जिंदगी के जंजाल में बेहद जरूरी है दिमागी सुकून, आप भी अपना सकती हैं ये उपाय

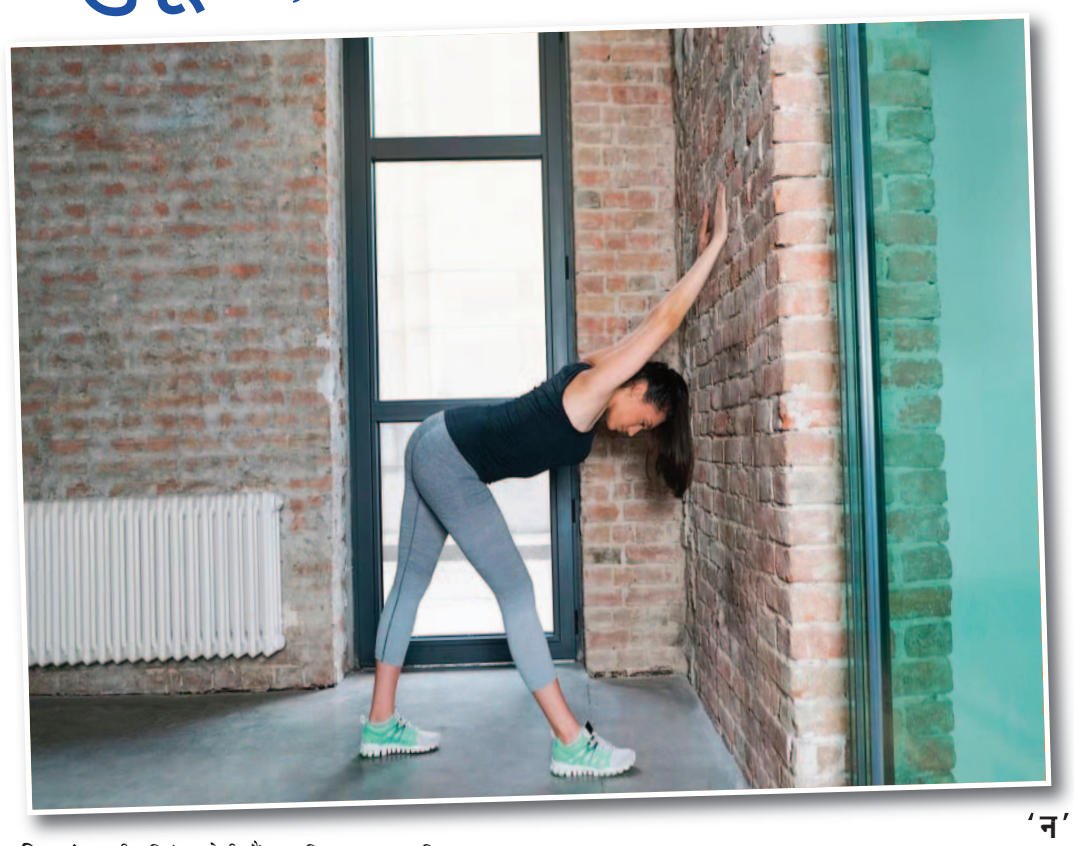

महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, इसलिए उनका मस्तिष्क अत्यधिक काम करता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग लाल झंडी दिखा रहा है और आपसे कुछ जगह खाली करने की मांग कर रहा है। अलमारियों की तरह हमारे दिमाग को भी समय-समय पर साफ-सफाई की जरूरत होती है। प्रेरक और कुशल बने रहने के लिए सभी गैर-जरूरी मानसिक बोझ से छुटकारा पाना जरूरी है।

दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ सरल, मगर बेहद प्रभावी युक्तियां मौजूद हैं। सुकून के पल जीने और मानसिक बोझ से बचने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रकार के कामों को अपने जीवन में शामिल कर सकती हैं। याद रखें, हर किसी का सफर अनोखा होता है और आप अपनी परिस्थिति के अनुसार इन तरीकों का पालन कर अपनी मुश्किलें कम कर सकती हैं।

प्राकृतिक मूड बूस्टर

मानसिक परेशानी से बचने के लिए आप खुद को भी समय दें। ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दें, जो आराम को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि ध्यान, योग और हल्के व्यायाम। नियमित व्यायाम से कई मानसिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर है। अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में रचनात्मक कार्यों को भी शामिल करें। खुद को लेखन, पेंटिंग, नृत्य और संगीत में लगाए रखें। इससे तनाव कम होता है।

'न' कहना सीखें

सीमाएं निर्धारित करना सीखें और आवश्यकता पड़ने पर 'न' कहना सीखें। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संरक्षित करेगा। इसके अलावा अपने विचारों और भावनाओं के प्रति आलोचनात्मक न होकर खुद को शांत रखें। अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए कार्यों की सूची बनाएं। डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करें। इससे हर तरह के हालात पर नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा और तनाव कम होगा।

एक सपोर्ट नेटवर्क

मित्रों, परिवार या साथियों के साथ एक सपोर्ट नेटवर्क से जुड़ें। अपनी मुश्किलों को दूसरों के साथ साझा करने से मानसिक बोझ कम होता है और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। अपने आस-पास ऐसे सकारात्मक और सहयोगियों को रखें, जो आपको आगे बढ़ने मदद करें और प्रेरित करें। जीवन के सकारात्मक पहलुओं को याद करते हुए सहयोगियों का आभार भी जताएं। इससे संतुष्टि और शांति मिलेगी।

तकनीक से दूरी

सूचनाओं के मकड़जाल से बचने के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लें। समाचारों, सूचनाओं और ऑनलाइन खबरों के लगातार संपर्क में रहने से मानसिक थकान हो सकती है।

गोवा में ऐसे कपड़े पहनकर दिखाएं अपना जलवा, हर कोई देखकर करेगा तारीफ

आपने भी कभी न कभी तो एक बार अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने का प्लान बनाया ही होगा। बहुत से युवा तो अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप मार भी चुके हैं। जो लोग दोस्तों के साथ गोवा नहीं जा पाते, वो अक्सर शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं।

गोवा एक ऐसी जगह है, जहां जाने के लिए आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। दरअसल, यहां कई बीच यानी कि समुद्र तट हैं। ऐसे में आप बीच पर कुछ भी हैवी पहनकर नहीं जा सकते।

लड़के तो सिंपल से शॉर्ट्स और टीशर्ट पहनकर अपना जलवा दिखा देते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए स्टाइलिश बीच लुक कैरी करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज के लेख में हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के लुक्स दिखाने जा रहे हैं, जिनसे टिप्स लेकर आप गोवा जाने की शॉपिंग कर सकती हैं।

क्रिस्टल डिसूजा

बीच पर ग्लैमरस दिखने के लिए आप क्रिस्टल डिसूजा के लुक्स से टिप्स ले सकती हैं। इस तरह की स्लिट स्कर्ट और ब्रालेट स्टाइल की टॉप आपके लुक में चार चांद लगाने का काम करेगी।

रुबीना दिलैक

अगर क्यूट दिखना चाहती हैं तो आप रुबीना के लुक्स पर एक नजर डाल सकती हैं। इसके लिए आपको बस इसी तरह की क्यूट सी शॉर्ट ड्रेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसी ड्रेस के साथ पैरों में स्लीपर और सिर पर हैट लेना कतई न भूलें।

अनीता हसनंदानी

बहुत सी लड़कियों को शॉर्ट्स कैरी करना पसंद होता है क्योंकि ये काफी आरामदायक होता है। ऐसे में अनीता के इस लुक से टिप्स लेकर आप क्यूट सी टॉप और डेनिम शॉर्ट्स कैरी कर सकती हैं।

सुरभि चंदना

ऐसी वन शोल्डर टॉप और फ्लोरल प्रिंट की स्लिट वाली स्कर्ट आपको खूबसूरत दिखने में मदद करेगी। इसके साथ आंखों पर अगर आप चश्मा लगाएंगी तो आपका अंदाज हॉट दिखेगा।

सोनारिका भदौरिया

अगर आप अपने पार्टनर के साथ गोवा जा रही हैं तो इस तरह के आउटफिट साथ जरूर ले जाएं। शॉर्ट ड्रेस के अलावा लाल रंग की मिनी स्कर्ट और व्हाइट रंग की पारदर्शी शर्ट आपको ग्लैमरस दिखने में मदद करेगी।

जेनिफर विंगेट

अगर आपको बॉडीकॉन ड्रेस पहनना पसंद है तो आप जेनिफर के जैसी हल्के फैब्रिक की बॉडीकॉन कैरी कर सकती हैं। इसके साथ अपने बालों को खुला रखें और मेकअप का खास ध्यान रखें।

कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को दूर कर सकती है सरकार

शेयर बाजार से प्राप्त लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर समान टैक्स करने की खबर चल जाने से गत शुक्रवार को बाजार में 1000 अंक से अधिक की गिरावट हो गई। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक्स पर कहना पड़ा कि यह बात पूरी तरह से अफवाह है। हालांकि टैक्स विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कई चीजें अस्पष्ट और जटिल हैं।

शेयर बाजार से प्राप्त लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर समान टैक्स करने की खबर चल जाने से गत शुक्रवार को बाजार में 1,000 अंक से अधिक की गिरावट हो गई। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक्स पर यह कहना पड़ा कि यह बात पूरी तरह से अफवाह है और इस मामले में वित्त मंत्रालय से सच्चाई जानने की आवश्यकता है।

हालांकि टैक्स विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कई चीजें अस्पष्ट और जटिल है जिसे साफ और करदाताओं के लिए आसान बनाने की आवश्यकता है। उम्मीद की जा रही है नई सरकार के गठन के बाद इनमें बदलाव की संभावना है।

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर ही नहीं लगता है, म्युचुअल फंड, प्रोपर्टी की बिक्री, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर के हस्तांतरण जैसी कई चीजों पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इनसे जुड़े टैक्स में जटिलताएं हैं जिसे करदाता ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए नई सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) को लेकर भी डिडक्टर को समस्याएं आ रही हैं और इनमें भी बदलाव हो सकता है। बड़ी संख्या में टीडीएस डिडक्टर को नोटिस आ रहे हैं।

किस तरह की होती है दिक्कत?

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के पार्टनर विवेक जालान ने बताया कि अप्रत्यक्ष कर की दुरुस्त व्यवस्था के लिए जीएसटी प्रणाली लाई गई, वैसे ही प्रत्यक्ष कर एवं उससे जुड़े कैपिटल गेन टैक्स, टीडीएस से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने के लिए नई सरकार प्रत्यक्ष कर की नई संहिता ला सकती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि प्रोपर्टी बेचने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसकी गणना को लेकर अस्पष्टता है।

मान लीजिए 31 मार्च को प्रॉपर्टी बेचने का राजीनामा हुआ और कुछ एडवांस लिया गया। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अप्रैल या मई में हुई तो कैपिटल गेन का वित्त वर्ष कौन सा होगा, इसे लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं क्योंकि राजीनामा व रजिस्ट्री का वित्त वर्ष बदल गया। म्युचुअल फंड में निवेश पर होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी छोटे निवेशकों को साफ जानकारी नहीं है।

कैपिटल गेन टैक्स में सुधार की जरूरत

टैक्स विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) असीम चावला कहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में सुचारू सुधार की जरूरत है और इसे करदाताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हस्तांतरण के मूल्यांकन व उस पर टैक्स निर्धारित जैसी कई चीजें अभी जटिल हैं।

शेयर बाजार में शेयर खरीदने के 12 माह से कम समय में शेयर की बिक्री कर मुनाफा कमाते हैं तो उसे शार्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है और मुनाफे पर 15 प्रतिशत टैक्स सरकार लेती है। एक साल के बाद बिक्री पर होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म मुनाफा कहा जाता है जिस पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगता है

आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, क्या 48 लाख कर्मियों, 65 लाख पेंशनरों को करना होगा और इंतजार?

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह बात साफ कर दी है कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव, सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीए/डीआर की दर 53 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर पचास प्रतिशत के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन, कई बार सरकार से आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस साल के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इस बाबत सरकार मौन रही।

संसद सत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब में कहा, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष भी संसद सत्र के दौरान भी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया था कि आठवें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही।

पूर्व के संसद सत्र में चौधरी ने वेतन आयोग के गठन को लेकर पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था और तीस वर्ष से महंगाई का सामना, यह तर्क भी दिया था। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया है। भारत पेंशनर समाज (बीपीएस) ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा था, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए।

देश में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ चुके हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी। तीसरे, चौथे और पांचवें सेंट्रल पे कमीशन 'सीपीसी' ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को सीपीसी गठित करने के लिए दस वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आईआरटीएसए के अनुसार, सातवें वेतन आयोग ने कहा है कि सीपीसी के गठन के लिए दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, गत दस वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति, आदि में कई बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं में निजी क्षेत्रों की भूमिका और उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव, आदि भी देखे गए हैं।

स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए का आंकड़ा अब 53 प्रतिशत हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग का गठन न होने से देशभर के दो करोड़ सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 'भारत पेंशनर समाज' ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है।

बतौर सुभाष लांबा, 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से केन्द्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केन्द्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी।

साउथ कोरिया में मार्शल लॉ हटाने का ऐलान, राष्ट्रपति यून ने वापस लिया आदेश

सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मंगलवार देर रात देश में लगाए गए मार्शल लॉ को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला संसद के भारी विरोध और मतदान के बाद लिया गया। मतदान के दौरान 300 में से 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से मार्शल लॉ को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। मार्शल लॉ का ऐलान होने के बाद जनता सड़क पर उतर आई थी। आर्मी के टैंक सियोल की गलियों में घूमते हुए नजर आए थे। बिगड़ते हालातों और लगातार विरोध के चलते राष्ट्रपति ने अपना फैसला वापस ले लिया।

सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने किया विरोध

देश में मार्शल लॉ लागू होने के बाद से ही सत्तारूढ़ और विपक्षी दल इसके विरोध में उतर आए। सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने भी इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानकि बताया। वहीं राष्ट्रपति की अपनी पार्टी के नेता हैन डोंग-हून ने भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की और संसद में हुए मतदान में भी हिस्सा लिया।

क्या बोले राष्ट्रपति यून

इस बीच यहां यह भी बता दें कि, राष्ट्रपति यून सुक-योल के मार्शल लॉ के फैसले के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे थे। हालांकि, अपने इस कदम पर सफाई देते हुए राष्ट्रपति यून ने कहा कि यह फैसला देश विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए लिया गया था।

पहले भी लगाया गया था मार्शल लॉ

दक्षिण कोरिया में करीब पांच दशक बाद मार्शल लॉ लगाया गया था। आखिरी बार 1980 में ऐसा हुआ था। यहां यह समझना जरूरी है कि दक्षिण कोरिया एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है। यहां चार दशकों से भी अधिक समय से लोकतंत्र रहा है। ऐसे में मार्शल लॉ लागू करने के कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा हो गई थी।

कौन हैं यून सुक-योल, जिनके एक फैसले से साउथ कोरिया में मचा बवाल, सड़कों पर उतरी जनता

सियोल। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मंगलवार को देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही पूरे देशभर में विरोध देखने को मिला। मार्शल लॉ के विरोध में संसद में भी काफी हंगामा देखने को मिला। आम जनता मार्शल लॉ के विरोध में सड़क पर उतर आई, जिसके बाद मार्शल लॉ को लेकर संसद में वोटिंग कराई गई।

वोटिंग के जरिए नेशनल असेंबली के 190 सदस्य ने मार्शल लॉ को हटाए जाने को लेकर वोट किया। इसके बाद, इन सब बवाल के बीच आखिरकार राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस ही लेना पड़ा। फैसला वापस लेने के बाद से ही राष्ट्रपति यून सुक-योल चर्चा में हैं, आइये जानते हैं कब राष्ट्रपति चुने गए थे। जिन्होंने सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को आखिरी बार 1980 में राजनीतिक उथल-पुथल के समय लागू किया गया था। उस समय ग्वांगजू विद्रोह हुआ था। 1948 से अब तक दक्षिण कोरिया में एक दर्जन से अधिक बार मार्शल लॉ लगाया गया है।

कौन हैं राष्ट्रपति यून सुक-योल?

राष्ट्रपति यून सुक-योल का जन्म 18 दिसंबर 1960 को हुआ था। जो 2022 से दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इसके पहले उन्होंने 2019-2021 तक देश के अटॉर्नी जनरल जनरल के रूप में काम किया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल 27 सालों तक एक वकील के रूप में काम करते रहे। योल साल 2022 के मई महीनें में 1% से कम मार्जिन से राष्ट्रपति चुने गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार योल की जनता के बीच लोकप्रियता काफी कम रही है। पिछले कई महीनों से योल की समर्थन रेटिंग महज 20% बनी हुई है। यही कारण है कि इसी साल अप्रैल में हुए चुनावों में उनकी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष का अब लगभग दो तिहाई सीटों पर कब्जा है। जिसके बाद एक सदनीय सभा पर विपक्ष का कब्जा हो गया।

सबसे ज्यादा बार किया वीटो पावर का इस्तेमाल

चुनाव में मिली हार के बाद से ही योल दबाव में थे। डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार उनकी पत्नी की के कथित घोटालों की जांच के लिए विधेयक पारित कर रही थी। योल ने इसको लेकर बार-बार विधेयकों पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया। साउथ कोरिया में 1987 में सैन्य शासन के बाद राष्ट्रपति यून सुक-योल पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार वीटों पावर का इस्तेमाल किया है।

सेंसर की समस्या-चार्जिंग में विस्फोट... क्या खत्म हो जाएगा टेस्ला का क्रेज?

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईवीएम की बात तो ठीक है.. ईवी का क्या?... भारत की ईवीएम की बात करने वाले एलन मस्क को अब उनकी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों से झटका लगा है? टेस्ला को ईवी इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाला ब्रांड माना जाता है। फिलहाल अब ये कंपनी तकनीकी खामियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण विवादों के घेरे में है। एलन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने अपनी हाई-टेक तकनीक और सेल्फ-ड्राइविंग फीचर्स के दम पर वैश्विक बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी जरूर हासिल की है। लेकिन हाल के हादसों और तकनीकी खामियों ने इसकी ब्रांड इमेज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

एलन मस्क ने 2026 तक पूरी तरह से अपने आप बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली कारें लाने का वादा किया है। लेकिन, मौजूदा टेस्ला वाहनों में सामने आ रही समस्याओं ने

इन वादों की विश्वसनीयता पर संदेह खड़ा कर दिया है। टेस्ला की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक में सेंसर और कैमरों की कमी की शिकायतें आम हो गई हैं। वाहनों के लाल और हरी बत्तियों का पालन न करने, और अचानक ब्रेकर्स का पता न लगा पाने जैसी घटनाएं सड़क हादसों का कारण बन रही हैं।

सड़क हादसे ही नहीं, टेस्ला की गाड़ियों की बैटरी को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान वाहनों के ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में, एक मामला तब सुर्खियों में आया जब एक टेस्ला वाहन चार्जिंग के दौरान फट गया, जिससे वाहन के साथ घर भी नष्ट हो गया। इन घटनाओं ने चार्जिंग प्रक्रिया और बैटरी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

टेस्ला की लोकप्रियता और विवादों का असर

टेस्ला की गाड़ियां देखने में आकर्षक और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। वैश्विक बाजार में इसकी जबरदस्त मांग है, खासतौर पर अमेरिका में, जहां यह अनिवासी भारतीयों की पसंदीदा कार बन चुकी है। लेकिन, इसके साथ जुड़े हादसे और चार्जिंग संबंधी समस्याएं इसके ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। टेस्ला वाहनों के दो ड्राइविंग मोड हैं। एक मैनुअल और दूसरा ऑटो मोड स्टियरिंग। ऑटो मोड में हादसे अधिक हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अरब में फिर दिखेगी तबाही ही तबाही, क्या लेबनान में जंग का शुरू होगा फेज-2?

यरुशलम, एजेंसी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम अब आधिकारिक तौर पर टूट चुका है। इजराइल की सेना IDF और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। सीजफायर टूटने से अरब में दहशत है। डर है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग एक बार फिर छिड़ सकती है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये लेबनान जंग का सबसे विध्वंसक दौर होगा।

जिस बात की आशंका थी, वही हुआ। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुआ सीजफायर अब टूट चुका है। 27 नवंबर को युद्धविराम की जिस डील पर साइन हुए थे। वो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया और अब दोनों खेमों ने ना सिर्फ युद्धविराम खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बल्कि एक दूसरी पर बारूदी बारिश भी शुरू कर दी है।

2 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर एयरस्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में

आज हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पलटवार का ऐलान किया और मोर्टार से हमले किए। दावा है कि IDF ने नाबातिह में फाइटर जेट से बम बरसाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ड्रोन से भी हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के शहरों में इजराइली ड्रोन की आवाजें साफ-साफ सुनी जा सकती हैं।

इजराइल ने युद्धविराम का 54 बार उल्लंघन किया

इजराइली हमले का जवाब हिजबुल्लाह भी उसे के अंदाज में दे रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रोयात अल-आलम बेस पर हमले किए। इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर मोर्टार से हमला किया। हिजबुल्लाह के आक्रामक रुख के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल किसी भी लेबनान पर बड़ी एयरस्ट्राइक का दौर शुरू कर सकता है। इसके साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है।

इन कयासों की वजह इजराइल सेना प्रमुख हर्जी हलेवी की कुछ तस्वीरें मानी जा रही है। दरअसल, हर्जी हलेवी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे और यहां जवानों से बात की। दावा है कि इस दौरान उन्होंने जवानों से सैन्य रणनीति पर भी चर्चा की। सवाल है कि ये सीजफायर टूटा किसकी वजह से, पहला हमला किसने किया, इसे लेकर लेबनान का दावा है कि इजराइल ने युद्धविराम का 54 बार उल्लंघन किया है। वहीं, इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने माउंट डोव पर रॉकेट से हमला किया।

इजराइल कभी भी कर सकता है ऑपरेशन शुरू

सीजफायर टूटा किसकी वजह से, इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इजराइल किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से मिलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि माउंट डोव पर हिजबुल्लाह की गोलीबारी संघर्ष विराम का गंभीर उल्लंघन है। हम सीजफायर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के किसी भी हमले का करारा जवाब जरूर देंगे।

एक तरफ बेंजामिन जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। दोनों तरफ से मिल रहे विनाशक संकेतों से पूरे अरब में दहशत है। माना जा रहा है कि लेबनान जंग का फेज-2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस बार तबाही पहले से कहीं ज्यादा भीषण होगी।

'..मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा', देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। वे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस पांच सितंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे और अजित पवार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के नारे 'एक है तो सेफ हैं' को

भी दोहराया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना यान तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि उन्होंने यह बयान 2019 में दिया था।

फडणवीस का पुराना बयान हुआ वायरल

भाजपा नेता और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस का यह बयान 2019 का है, जो 2024 के विधानसभा के नतीजे आने के बाद फिर से वायरल हो रहा है। उन्होंने 2019 के चुनाव में कहा था, ₹मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा।₹ उन्होंने अपने इस बयान को पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के साथ साझा किया था। वीडियो में उनके इस बयान को उनके आवाज के साथ बड़े-बड़े शब्दों में लिखा भी गया था।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 132 से ज्यादा सीटें जीती। वहीं अगर भाजपा नीत महायुति के घटक दलों की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की राकांपा 41 सीटें जीतने में कामयाब रही। महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ 46 सीटें जीतीं। जिसमें कांग्रेस ने 16 और शिवसेना ने 20 सीटें जीतीं।

महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच था मुकाबला

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बनी महायुति गठबंधन का कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) से मिलकर बने विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी से था। जबकि राज्य में सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक चरण में वोट डाले गए थे। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव में कुल 65.11 फीसदी वोटिंग हुई थी, जो पिछले (साल 2019) विधानसभा चुनाव के (61.44 फीसदी) मुकाबले कुल 3.67 फीसदी ज्यादा है।

कोल ब्लॉक आवंटन पर सुनवाई कर सकें हाईकोर्ट, इसके लिए आदेश में सुधार करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने अपने उस आदेश में सुधार करेगा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट अवैध कोल ब्लॉक आवंटन के मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से 2017 के बीच दो आदेश जारी किए थे, जिसके जरिए आरोपियों के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचने पर रोक लगा दी गई थी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोयला घोटाले से जुड़े मामलों में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ सिर्फ उसके पास ही याचिका लगाई जा सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मकसद सुनवाइयों में होने वाली देरी पर रोक लगाना था। इसके साथ ही कोर्ट राहत की मांग के जरिए आरोपियों की कार्यवाहियों को रोकने की कोशिशों पर लगाम लगाना चाहती थी। हालांकि, अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा है कि वह अपने पिछले आदेश में सुधार करने पर विचार करेगी।

'मामले की तह तक जाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सदस्यीय समिति का करें गठन', लापता शख्स को लेकर हाईकोर्ट

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के लीमाखोंग कैंप से 25 नवंबर को लापता हुए 56 साल के लैशराम को सेना और पुलिस के हजारों जवान मिलकर खोज रहे हैं। मणिपुर पुलिस ने बताया था कि लैशराम का पता लगाने के लिए वह हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और सेना के ट्रैकर कुत्तों की मदद ले रही है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। फिर भी व्यक्ति का कुछ पता नहीं लग रहा है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति गोलमेई गैफुलसिलु काबुई की खंडपीठ ने मंगलवार को सुझाव दिया कि कांगपोकपी जिले के जिला मजिस्ट्रेट, कांगपोकपी के पुलिस अधीक्षक, इंफाल पश्चिम के पुलिस अधीक्षक और 57 माउंटेन डिवीजन के कमांडिंग अधिकारी की एक समिति गठित की जाए और एक रिपोर्ट तैयार करे। अदालत ने आदेश दिया कि 11 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर समिति अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पीठ ने कहा कि समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेगा। वह लापता शख्स के संबंध में जांच करेगी। साथ ही यह पता लगाएगी कि शख्स का शिविर से अपहरण तो नहीं कर लिया गया या वह खुद से कही चला गया है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का परिवार उनके पास उपलब्ध किसी भी सामग्री या रिकॉर्ड को पेश करने के लिए समिति के साथ सहयोग करेगा और समिति के प्रमुख याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को जांच के लिए समिति के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस देंगे।

कांगपोकपी जिले में बना 57वें माउंटेन डिवीजन लीमाखोंग आर्मी कैंप राजधानी इंफाल से लगभग 16 किमी दूर है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह एक कुकी बहुल इलाका है। लैशराम, अपने परिवार के साथ इंफाल पश्चिम के खुखरुल में रहते थे। पिछले साल मई में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद लीमाखोंग के पास रहने वाले मैतेई लोग भाग गए थे, जिनमें अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। असम के कछार में उधारबोंड के गोसाईपुर रहने वाले लैशराम कमलबाबू सिंह, मेसर्स एल बिनोद कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे।

भाजपा को फिर बड़ा झटका, बड़े नेता प्रवेश रत्न आप में शामिल, केजरीवाल के कामों से थे प्रभावित

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। एक बार फिर भाजपा को दिल्ली में आप ने बड़ा झटका दिया है। अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर जाटव समाज के बड़े नेता प्रवेश रत्न आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

आप के बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने प्रवेश रत्न के आप में

शामिल होने पर कहा कि समस्त जाटव समाज आम आदमी पार्टी के साथ है। आप सरकार के कामों से जाटव, दलित और एससी समाज के परिवारों को काफी लाभ हुआ है। उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है। आज अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर भाजपा नेता प्रवेश रत्न आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मैं उनका स्वागत करता हूं।

आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद प्रवेश रत्न ने कहा कि केजरीवाल की छह रेवड़ियों से जाटव समाज को लाभ हुआ है। दिल्ली में आप सरकार शिक्षा समेत तमाम चीजों को लेकर शानदार काम कर रही है। मैं अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूं। केजरीवाल की 6 रेवड़ियों से जाटव और ग़रीब समाज की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है। इसे और आगे बढ़ाने को लेकर हम मिलकर काम करेंगे।

कोई 1200 तो किसी ने की 850 करोड़ से ज्यादा कमाए, ये 10 फिल्में चीन में रिलीज हुई तो मालामाल हो गए प्रोड्यूसर्स

बॉलीवुड की कुछ फिल्में तीन में रिलीज की जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए चीन अब एक बड़ा मार्केट बन चुका है, क्योंकि चीन में फिल्मों की कमाई भारत की तुलना में ज्यादा हो जाती है। 'दंगल' चीन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

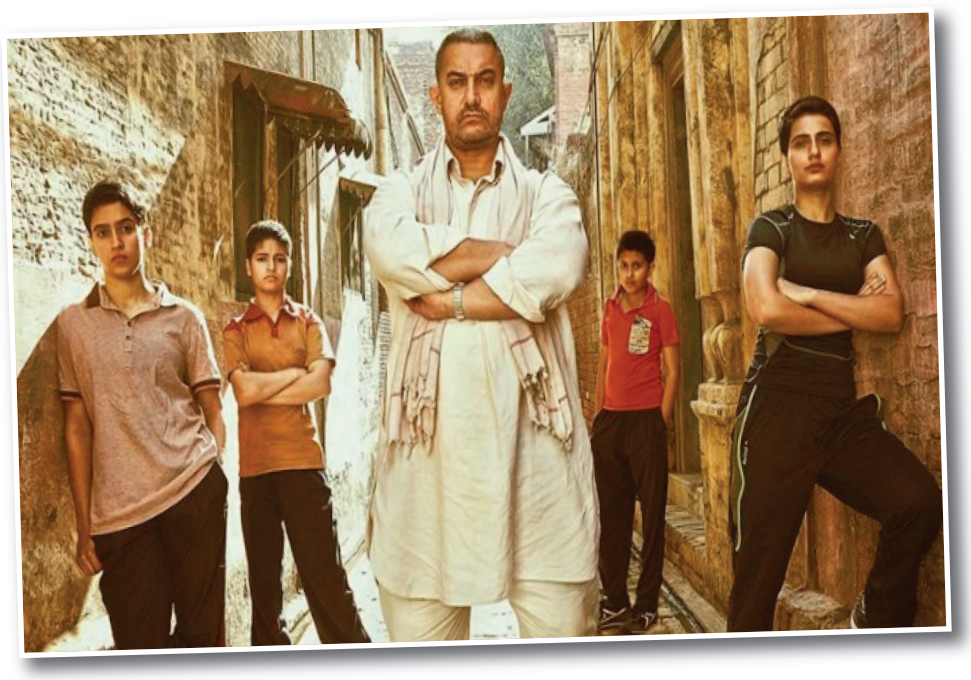

बॉलीवुड की फिल्मों को देशभर में तो काफी पसंद किया जाता है, लेकिन अब बॉर्डर के उस तरफ भी फिल्मों का एक अच्छा मार्केट बन चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश चीन की जो कि फिल्मी दुनिया के लिए पिछले कुछ सालों से एक बड़े मार्केट के तौर पर सामने आया है। पिछले कुछ सालों में कई हिंदी फिल्म चीन के थिएटर में रिलीज हुई है, जो कि कमाई के मामले में काफी अच्छी रही हैं। कई फिल्मों ने भारत में भी उतनी कमाई नहीं की, जितनी चीन में कर ली है। चीन में फिल्मों की ज्यादा कमाई की सबसे बड़ी वजह स्क्रीन है। दरअसल, भारत में ज्यादा से ज्यादा 8 हजार स्क्रीन्स पर फिल्मों को दिखाया जा सकता है, वहीं चीन में स्क्रीन भारत से 5 गुना से भी ज्यादा है। चीन में स्क्रीन की संख्या तकरीबन 45 हजार है। इसी वजह से भारत के मुकाबले फिल्में चीन में ज्यादा कमाई करती हैं। हाल ही में चीन में विजय सेतुपति की फिल्म 'महाराजा' रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आइए चीन में रिलीज हुई बाकी फिल्मों की कमाई के बारे में जानते हैं।

दंगल

आमिर खान, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा स्टारर 'दंगल' चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, जो कि 70 करोड़ के बजट पर बनी थी। भारत में इस फिल्म ने 538 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं चीन में इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।

सीक्रेट सुपरस्टार

साल 2017 में जायरा वसीम की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' आई थी, ये फिल्म ज्यादा बजट वाली नहीं थी। भारत में सीक्रेट सुपरस्टार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म ने 81V28 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन वहीं चीन में कमाई के मामले में इसने कमाल कर दिया था। सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन में भारत के मुकाबले 10 गुना कमाई की थी। इस फिल्म ने चीन में 863 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

अंधाधुन

आयुष्मान खुराना, तबू और राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'अंधाधुन' बेहतरीन फिल्मों में आते हैं। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी और उस वक्त इस फिल्म ने भारत में 96 करोड़ रुपए का कमाई की थी। वहीं चीन में इस फिल्म ने 333V62 करोड़ की कमाई की थी।

हिचकी

रानी मुखर्जी की फिल्म 'हिचकी' साल 2018 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म को चीन में 'माय टीचर विथ हिकप्स' के नाम से रिलीज किया गया था। भारत में इस फिल्म ने 59 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं चीन में इस फिल्म ने 156.66 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।

पीके

आमिर खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म 'पीके' ने थिएटर में काफी धमाल मचाया। इस फिल्म में दोनों ही एक्टर्स की खूब तारीफ की गई। भारत में इस फिल्म ने 507 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं चीन में पीके ने 128.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।

मॉम

बोनी कपूर की बनाई फिल्म 'मॉम' साल 2017 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में श्रीदेवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सजल अली लीड रोल में थे। भारत में इस फिल्म ने 51.80 की कमाई की वहीं चीन की बात करें तो इसने 122.04 करोड़ रुपए की कमाई की।

टॉयलेट : एक प्रेम कथा

अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'टॉयलेटः एक प्रेम कथा' साल 2017 में आई थी। ये फिल्म सोशल इशू पर बनी थी। भारत में इस फिल्म ने 186.42 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन चीन में इसने थोड़ी कम

बजरंगी भाईजान

सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने भारत में ही काफी तारीफ बटोरी थी। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। भारत में इस फिल्म ने 432.46 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन चीन में इसकी कमाई बाकी फिल्मों के मुकाबले कम थी, जो कि 295.76 करोड़ रुपए थी।

हिंदी मीडियम

इरफान खान और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर स्टारर 'हिंदी मीडियम' साल 2017 में आई थी। ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा थी, भारत में इस फिल्म 96.65 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं चीन में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने 219.17 करोड़ रुपए की कमाई की।

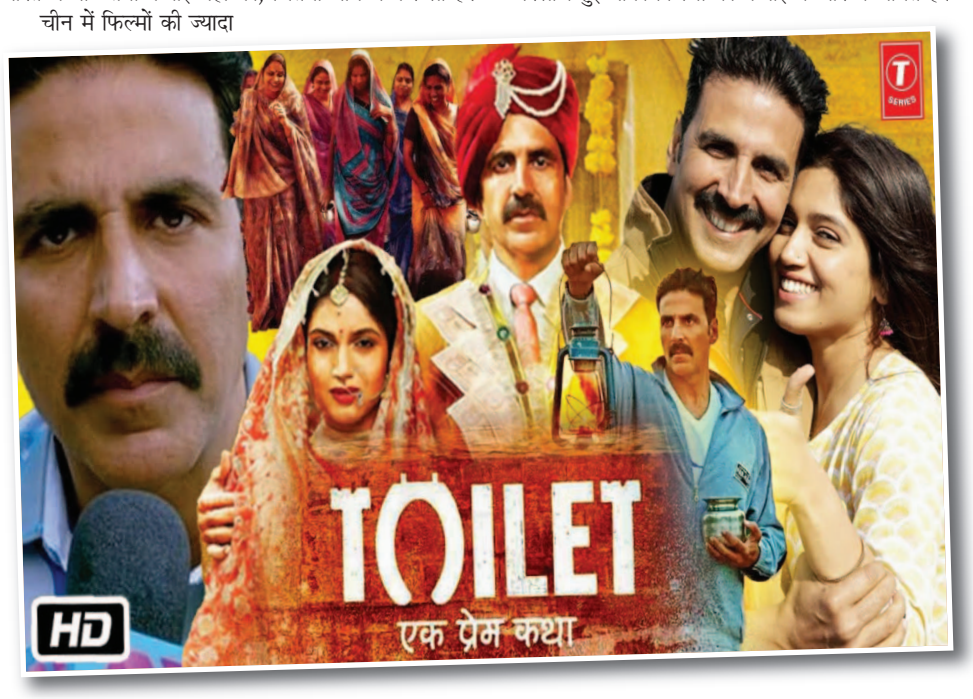

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com